TV उत्तरशक्ति NEWS
मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित
हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
हर खबर निष्पक्षता के साथ
मुंबई
वर्ष: 8 अंक 200
मंगलवार, 03 फरवरी 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

धर्मांतरण कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और 12 राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 02 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 फरवरी 2026) को धर्मांतरण रोधी कानूनों को लेकर एक अहम सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और देश के 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है। यह मामला नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया की ओर से दायर नई जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें कई राज्यों के Anti-Conversion Laws को संविधान के खिलाफ बताया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संवेदनशील मुद्दे की आगे की सुनवाई अब तीन जजों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी।

NCCI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को बताया कि कई राज्यों में लागू धर्मांतरण कानूनों का व्यापक दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका तर्क था कि इन कानूनों के चलते आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों–अनुच्छेद 14 (समानता), 21 (जीवन व स्वतंत्रता) और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) का गंभीर उल्लंघन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के कानून ऐसे हैं, जो समूहों को शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे बिना ठोस आधार के FIR, पुलिस कार्रवाई और उत्पीड़न बढ़ रहा है। इसी आधार पर याचिकाकताओं ने इन कानूनों पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार अपना जवाब जल्द दाखिल करेगी। उन्होंने दलील दी कि ये कानून पहले से मौजूद सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच के पुराने फैसलों के दायरे में आते हैं।

इस पर मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत का ध्यान ओडिशा और राजस्थान में हालिया संशोधनों की ओर दिलाया और कहा कि ये नए बदलाव पहले की याचिकाओं में शामिल नहीं थे। उन्होंने सभी राज्यों के स्थायी अधिवक्ताओं को औपचारिक नोटिस देने की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा जिन 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है, वे हैं– राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। अदालत ने निर्देश दिया है कि नोटिस की प्रति संबंधित राज्यों के महाधिवक्ताओं (Advocate General) को भी भेजी जाए। साथ ही सभी राज्य चाहें तो संयुक्त जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इन कानूनों की संवैधानिक वैधता से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सितंबर 2025 में भी अदालत ने कुछ मामलों में राज्यों से जवाब तलब किया था।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत अंतरिम राहत देती है या नहीं।

वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आए 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, सेल्फी लेने के चक्कर में गंवाई जान

राजकोट, 02 फरवरी। गुजरात के राजकोट शहर के नजदीक सोमवार शाम को रेलवे पटरी के करीब 'ग्रुप सेल्फी' लेते समय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

अजी डैम पुलिस थाना के उप निरीक्षक एआर राठौड़ ने बताया कि यह घटना शाम 4:45 बजे भक्तिनगर और रिबदा स्टेशन के बीच एक रेलवे फाटक के पास उस समय हुई, जब वेरावल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजर रही थी। उन्होंने बताया कि उस समय तीनों युवक अपने मोबाइल फोन से सेल्फी लेने के लिए पटरियों के करीब आ गए थे, लेकिन तभी वे तेज गति से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए।

अधिकारी के मुताबिक, तीनों पीड़ितों की उम्र 20 से 29 साल के बीच थी। राठौड़ ने बताया, "पटरियों से दूरी का गलत अनुमान लगाने के कारण तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए। घटना के बाद ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दो को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल में एक और युवक की मौत हो गई।"

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान संदीप पटेल और संदीप कोली के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान कपिल पटेल के रूप में हुई है। ये सभी उत्तर प्रदेश के निवासी थे और राजकोट में कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते थे। राठौड़ के मुताबिक, शुरूआती जांच में सामने आया है कि तीनों संदीप पटेल को छोड़ने स्टेशन जा रहे थे, जो अपने गांव जा रहा था। उप निरीक्षक राठौड़ ने बताया, "पटरी पार करते समय उन्होंने पटरियों के पास एक ग्रुप सेल्फी लेने का फैसला किया, लेकिन इसी दौरान वे ट्रेन की चपेट में आ गए।

किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर तीखा हमला

नई दिल्ली, 02 फरवरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसदीय नियमों का कथित उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के बार-बार निर्देश देने के बावजूद, कांग्रेस नेता अध्यक्ष को चुनौती देते रहे और विषय से भटकते रहे, जिसमें चीन सीमा का मुद्दा उठाना भी शामिल था। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। हम सभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए बैठे थे। लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और एक ऐसी किताब का हवाला देना शुरू कर दिया, जिसके प्रकाशन और प्रामाणिकता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

रिजिजू ने दावा किया कि रक्षा मंत्री और हम सभी ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलेगा और नियमों के अनुसार ही बोलना चाहिए... कोई अध्यक्ष को चुनौती नहीं दे सकता। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद भी राहुल गांधी वही गलती दोहराते रहे... उन्होंने आधा घंटा बर्बाद किया, नियमों का उल्लंघन किया और वही बात दोहराते रहे। उन्होंने चीन सीमा पर बोलना शुरू कर दिया... क्या कांग्रेस पार्टी 1959 और 1962 में चीन द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस ला सकती है? रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की और उन पर संसद से ऊपर खुद को रखने और बार-बार उसके नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो प्रक्रिया का पालन करता है, और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने व्यवधान को बढ़ावा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी को चीन सीमा मुद्दे से संबंधित पार्टी के पापों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

मुंबई के उद्योगपति राजेश प्रजापति ने राहुल गांधी को प्रजापति/कुंभकार समाज की समस्याओं से कराया अवगत

मुंबई/रायबरेली (उत्तरशक्ति)। प्रजापति समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान को लेकर मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं बिल्डर राजेश प्रजापति (अध्यक्ष, पीसीएसएफ) ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में विगत माह आयोजित प्रजापति समाज के एक सम्मेलन के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की।

इस अवसर पर राजेश प्रजापति ने देशभर में फैले प्रजापति, कुंभकार एवं कुम्हार समाज की विभिन्न समस्याओं से राहुल गांधी को अवगत कराया। उन्होंने समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने पूरे भारत में प्रजापति/कुंभकार समाज की

अनुमानित जनसंख्या से संबंधित तथ्यों को भी साझा किया।

उक्त सम्मेलन का नेतृत्व अवधेश कुमार प्रजापति द्वारा किया गया, जिसमें समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि नवी मुंबई में ''प्रजापति'' नाम से कई प्रमुख आवासीय भवनों का निर्माण कर चुके राजेश प्रजापति न केवल एक सफल बिल्डर हैं, बल्कि समाजसेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वह देशभर में प्रजापति समाज के जरूरतमंद एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, श्री प्रजापति समाजहित में निरंतर सामाजिक कार्य करते हुए युवाओं को शिक्षा, रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे समाज के समग्र विकास को नई दिशा मिल रही है। राजेश प्रजापति के इस सराहनीय कदम पर प्रजापति समाज मुंबई के अध्यक्ष प्रो. रामजन्म प्रजापति ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि समाजहित में आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए प्रजापति समाज सदैव आभारी रहेगा और भविष्य में भी आपसे और अधिक सक्रिय भूमिका की अपेक्षा रखता है।

सीएम हिमंता के 'मियां' बयान पर बवाल, हेट स्पीच बताकर जमात पहुंची सुप्रीम कोर्ट

असम। असम में मिया मुसलमानों को निशाना बनाकर कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मुख्यमंत्री के बयान को नफरत फैलाने वाला और दो समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने वाला बताया गया है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री द्वारा 27 जनवरी को दिए गए उस बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 4 से 5 लाख मिया मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की बात कही थी। याचिका में मिया शब्द के आपत्तिजनक प्रयोग का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि असम में इस शब्द का प्रयोग मुसलमानों के विरुद्ध अपमानजनक तरीके से किया जाता है। जमीयत ने सर्वोच्च न्यायालय से असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश देने की अपील की है ताकि भविष्य में कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति इस तरह के बयान न दे सके। सरमा ने तीखा बयान देते हुए कहा कि जब तक वह मुख्यमंत्री रहेंगे, 'मिया' समुदाय के लोगों को 'मुसीबत' का सामना करना पड़ेगा। सरमा ने यहां तक कह दिया कि अगर 'मिया' समुदाय के लोगों के लिए काफी परेशानियां खड़ी की गईं, तो वे राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए आमतौर पर 'मिया' शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरकारी कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा, अगर मैं असम में रहा, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, वे यहां शांति से नहीं रह सकते। अगर हम उनके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे, तभी वे राज्य छोड़ेंगे।

मुंबई (महाराष्ट्र)से प्रकाशित
हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
हर खबर निष्पक्षता के साथ

प्रजापति समाज के होनहार छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन

प्रजापति समाज मुंबई उच्च शिक्षा (चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून आदि) ग्रहण कर रहे समाज के मेधावी छात्रों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करा रहा है, ताकि छात्र-छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। छात्र 15 फरवरी 2026 या उससे पहले आवेदन करें।

निवेदक:
प्रोफेसर रामजन्म प्रजापति
(अध्यक्ष: प्रजापति समाज मुंबई)
गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया है-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsFwc2KBiq613bqOX5uPtAwZWdePD4_XZxB5kay0cNDO525g/viewform?usp=dialog

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की बात

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस संपर्क को भारत और अमेरिका के बीच लगातार बने हुए उच्चस्तरीय संवाद की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। बातचीत की पुष्टि भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर ने की है। सर्जियो गोर के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच हुई यह बातचीत द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम है। हालांकि, बातचीत के विषयों को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा विवरण साझा नहीं किया गया है, लेकिन राजनयिक हलकों में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नारी देह, नारी अधिकारः माहवारी पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

-ललित गर्ग

भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आधे हिस्से-महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी

स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मासिक धर्म स्वच्छता को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूली लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन का सवेतन पीरियड लीव नीति को भी मंजूरी दी है। यह फैसला स्कूलों में मासिक धर्म प्रबंधन की कमी को दूर करने और छात्राओं के सम्मानजनक शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला संदेश है कि अब माहवारी जैसे विषय को चुप्पी, लज्जा और अज्ञान के अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता।

विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में माहवारी के दौरान लड़कियों को रसोई, पूजा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। यह व्यवहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की गरिमा और अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि ह्लमाहवारी स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती हैह्व इस पूरे विमर्श को एक नई संवैधानिक दृष्टि देती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार को यदि वास्तविक अर्थों में लागू करना है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्कूलों में सेनेटरी पैड की अनिवार्य व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अध्ययन बताते हैं कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियाँ किशोरावस्था में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह केवल शिक्षा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक और नैतिक पूंजी की क्षति है।

न्यायालय ने शिक्षा को एक ह्यमल्टीप्लायर राइटह्ल बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन पैड्स का एएसटीएम डी-6954 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सहज, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वेंडिंग मशीन या नामित अधिकारी की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की झिझक और असहजता पूरी तरह दूर की जा सके। इसके साथ ही स्कूलों में ह्लमासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन कॉर्नरह्व स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, स्पेयर इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग और आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल शौचालय और सहायक उपकरण जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निदेर्शों की अवहेलना पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखकर जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर छात्रा के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके।

माहवारी स्वच्छता केवल पैड उपलब्ध कराने तक सीमित विषय नहीं है। इसके साथ जुड़ा है स्वच्छ शौचालय, साफ पानी, कचरा निस्तारण की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्णकृसही जानकारी। आज भी अनेक लड़कियाँ पहली माहवारी के समय भय, भ्रम और अपराधबोध से घिर जाती हैं क्योंकि उन्हें पहले से कोई वैज्ञानिक और संवेदनशील जानकारी नहीं दी जाती। स्कूलों में यदि स्वास्थ्य शिक्षा को गंभीरता से लागू किया जाए और माहवारी को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया जाए, तो यह डर और संकोच स्वतः समाप्त हो सकता है। यह भी सच है कि माहवारी को लेकर समाज में फैली चुप्पी पुरुषों की भूमिका को भी प्रश्नों के घेरे में लाती है। जब तक पुरुष-चाहे वे पिता हों, शिक्षक हों, प्रशासक हों या नीति-निमार्ता, इस विषय को केवल ह्लमहिलाओं का मामलाह्व मानकर किनारे करते रहेंगे, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने समाज और खासकर पुरुषों को संवेदनशील बनने का अवसर दिया है। जागरूकता का अर्थ केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं, बल्कि पुरुषों को सहृदय और जिम्मेदार बनाना भी है।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में माहवारी से जुड़ी चुनौतियाँ और भी गंभीर हैं। वहाँ आज भी कपड़े, राख या अस्वच्छ साधनों का उपयोग आम है, जिससे संक्रमण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सरकारी योजनाएँ और गैर-सरकारी प्रयास मौजूद हैं, परंतु उनकी पहुँच और प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यदि ईमानदारी से लागू होता है, तो यह नीति और जमीन के बीच की खाई को पाटने में सहायक हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि माहवारी स्वच्छता को केवल कल्याणकारी योजना न मानकर महिला अधिकारों के व्यापक ढाँचे में देखा जाए। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार-तीनों इस विषय से सीधे जुड़े हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ लड़की केवल इसलिए स्कूल न जा सके क्योंकि उसके पास सेनेटरी पैड नहीं हैं, वह व्यवस्था संविधान की आत्मा के विपरीत है। इसलिए यह फैसला सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी मजबूती देता है।

आज भारत ह्लनए प्रवेशह्व के साथ आगे बढ़ने की बात करता है-डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखता है। किंतु यदि इस विकास की गाथा में महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताएँ और सम्मान शामिल नहीं हैं, तो यह प्रगति खोखली सिद्ध होगी। वास्तविक विकास वही है जो सबसे कमजोर वर्ग की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का साहस रखे। माहवारी जैसे विषय पर खुली चर्चा उसी साहस का प्रतीक है। समाज में जन-जागृति लाना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कानून और आदेश दिशा दिखा सकते हैं, परंतु मानसिकता बदलना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मीडिया, शिक्षा संस्थान, धार्मिक और सामाजिक संगठन सभी को मिलकर माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ना होगा। इसे शर्म का नहीं, स्वास्थ्य और स्वाभिमान का विषय बनाना होगा। अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक शुरूआत है, मंजिल नहीं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं और कितनी संवेदनशीलता से अपनाते हैं। यदि हम सचमुच एक समावेशी, न्यायपूर्ण और मानवीय भारत का निर्माण चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के साथ नया भारत बनाना चाहते हैं तो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को विकास के केंद्र में रखना ही होगा। माहवारी से मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक सुविधा नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और संवैधानिक स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता किसी भी सभ्य और प्रगतिशील समाज की पहचान होती है।

ज्ञान, स्क्रीन और संवेदना का संकट

– डॉ. सत्यवान सौरभ

ज्ञान बढ़ा पर भाव क्या, अब भी मन लाचार–यह पंक्ति केवल एक दोहा नहीं, बल्कि इक्कीसवीं सदी के मनुष्य की सामूहिक आत्मस्वीकृति है। हमने जितना ज्ञान अर्जित किया है, उतना शायद मानव इतिहास के किसी भी कालखंड में नहीं किया गया। सूचनाएँ उँगलियों पर नाच रही हैं, दुनिया एक छोटे से स्क्रीन में सिमट आई है और विज्ञान ने जीवन को सुविधाओं की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है। इसके बावजूद–या शायद इसी कारण–मनुष्य भीतर से पहले से अधिक असहाय, असंतुलित और बेचैन दिखाई देता है। आज का संकट ज्ञान के अभाव का नहीं, बल्कि विवेक, संवेदना और ठहराव के लुप्त होने का संकट है।

स्क्रीन की चकाचौंध ने केवल हमारी आँखों को नहीं, हमारी चेतना को भी प्रभावित किया है। मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल माध्यमों ने सूचना को लोकतांत्रिक तो बनाया, पर सोच को गहराई नहीं दी। हम पहले से कहीं अधिक पढ़ते हैं, पर पहले से कहीं कम समझते हैं। हम देखते बहुत हैं, पर महसूस कम करते हैं। हर पल अपडेट रहना आज सचेत होने की पहचान बन गया है, लेकिन इसी निरंतर अपडेट ने मनुष्य को भीतर से थका और खाली कर दिया है। सोशल मीडिया पर विचार नहीं, प्रतिक्रियाएँ जन्म लेती हैं। वहाँ ठहराव नहीं, केवल तात्कालिक उत्तेजना है। सच और झूठ, गंभीरता और सतहीपन, संवेदना और सनसनी–सब एक ही मंच पर समान महत्व के साथ परोसे जा रहे हैं। ऐसे वातावरण में सतविचार, जो समय, मौन और आत्मसंवाद से उपजते हैं, धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं।

आज का मनुष्य ऐसे समय में जी रहा है जहाँ संवाद लगातार हो रहा है, पर संवादहीनता भी उतनी ही गहरी है। मोबाइल के कक्ष में आवाजें चिल्ला रही हैं–कॉल, मैसेज, वीडियो, मीटिंग्स, रील्स–हर ओर शोर है। लेकिन इसी शोर के बीच मनुष्य अपने ही भीतर की आवाज सुनने की क्षमता खो बैठा है। बाहर की बातचीत बढ़ी है, भीतर का संवाद घटा है। जब भीतर की खामोशी को सुना नहीं जाता, तो वह धीरे-धीरे कुंठा, आक्रोश और असंतुलन में बदल जाती है। आज रिश्तों में बढ़ता तनाव, समाज में बढ़ती असहिष्णुता, ऑनलाइन अपमान और वास्तविक जीवन में बढ़ती असंवेदनशीलता–ये सब उसी अनसुनी खामोशी के लक्षण हैं। हम बोलना जानते हैं, पर सुनना भूल चुके हैं। न दूसरों की पीड़ा सुन पाते हैं, न अपने मन की बेचैनी को समझ पाते हैं। संवाद की यह विफलता केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक भी है। जब समाज सुनना छोड़ देता है, तो असहमति शत्रुता में बदल जाती है और विचार विमर्श के स्थान पर टकराव जन्म लेता है। विज्ञान ने निस्संदेह मानव जीवन को अभूतपूर्व सुविधाएँ दी हैं। रोगों पर नियंत्रण, संचार की गति, यात्रा की सरलता और उत्पादन की क्षमता–इन सब क्षेत्रों में विज्ञान ने क्रांति की है। लेकिन इसी विज्ञान से यह अपेक्षा भी जुड़ी थी कि वह मनुष्य को अधिक संतुलित, अधिक संवेदनशील और अधिक जिम्मेदार बनाएगा। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हुआ। विज्ञान ने हमें शक्ति दी, पर संयम नहीं सिखाया। गति दी, पर विराम नहीं। साधन दिए, पर मर्यादा नहीं।

आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तकनीक हमें आगे बढ़ने के असंख्य रास्ते दिखाती है, पर यह नहीं बताती कि कब रुकना है। यह निर्णय विवेक करता है, और विवेक का विकास मशीनों से नहीं, मानवीय मूल्यों से होता है।

हमने ज्ञान को केवल संग्रहण तक सीमित कर दिया है। डिग्रियाँ बढ़ीं, पर दृष्टि संकुचित होती गई। विशेषज्ञता बढ़ी, पर समग्र समझ घटती चली गई। आज का शिक्षित व्यक्ति भीड़ में शामिल होने में तेज है, पर अकेले खड़े होकर सच बोलने में हिचकता है। यह शिक्षा का नहीं, सूचना के बोझ का परिणाम है। ज्ञान जब संवेदना से कट जाता है, तो वह अहंकार बन जाता है। तकनीक जब विवेक से कट जाती है, तो वह नियंत्रण के बजाय वर्चस्व का साधन बन जाती है। इस स्थिति का समाधान तकनीक को नकारने में नहीं, बल्कि उसे मानवीय मूल्यों के अधीन रखने में है। स्क्रीन से भागना संभव नहीं, पर उसके सामने नतमस्तक होना भी अनिवार्य नहीं। हमें फिर से मौन का महत्व समझना होगा। हमें संवाद को केवल बोलने की प्रक्रिया नहीं, सुनने की कला बनाना होगा। ज्ञान को आत्मचिंतन से जोड़ना होगा और विज्ञान को नैतिकता के साथ संतुलित करना होगा।

परिवार, शिक्षा और समाज–तीनों स्तरों पर यह पुनर्संरचना आवश्यक है। बच्चों को केवल स्मार्ट नहीं, संवेदनशील बनाना होगा। शिक्षा को केवल प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं, बल्कि मानवीय विकास का माध्यम बनाना होगा। समाज को यह स्वीकार करना होगा कि गति के साथ ठहराव भी उतना ही आवश्यक है। आज आवश्यकता किसी नए आविष्कार की नहीं, बल्कि पुरानी मानवीय समझ की पुनर्स्थापना की है। तकनीक हमारे जीवन का साधन बने, लक्ष्य नहीं। संवाद शोर नहीं, सेतु बने। और ज्ञान केवल बढ़े नहीं, मनुष्य को बेहतर बनाए। यदि हम यह संतुलन नहीं बना पाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ शायद अत्यंत उन्नत होंगी–पर भीतर से और भी अधिक लाचार।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

विकास की अनंत संभावनाओं के द्वार खोलेगा केन्द्रीय बजट

(डॉ. मोहन यादव -विभूति फीचर्स)

भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हम विकसित भारत का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 मध्यप्रदेश के लिए आर्थिक विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, उद्योगों को सरल प्रक्रियाएँ, निवेशकों को भरोसेमंद वातावरण, युवाओं को रोजगार के अवसर, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, एमएसएमई सेक्टर को संस्थागत समर्थन और नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्राप्त होंगी।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की जो नींव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रखी गई है उसे वर्ष 2026-27 के बजट ने और ज्यादा मजबूत किया है। भारत की अर्थव्यवस्था अब तेजी से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान शक्ति और उद्यमिता के सहयोग से भारत ने आगे बढ़ने जो संकल्प लिया है वह कई अर्थों में अद्भुत है। आज जब भारत औद्योगिक निवेश और निर्माण क्षेत्र का हब बनने जा रहा है, उसमें मध्यप्रदेश भी अपनी पूरी शक्ति के साथ योगदान देने के लिए तैयार है। हमने औद्योगिक निवेश के लिये अनूकुल वातावरण तैयार किया, जिससे निरंतर निवेश आ रहा है। नये बजट से पूरे इको-सिस्टम को नई ऊर्जा मिली है। बजट में हरित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है। इससे मध्यप्रदेश को दीर्घकालिक लाभ होने वाला है। कृषक कल्याण और कृषि विकास को मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। इसी प्रकार सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एआई आधारित तकनीक के विकास पर बजट में ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन तीनों क्षेत्रों में

मध्यप्रदेश को हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश और नवाचार आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। इन क्षेत्रों के लिये नीतियां बनाने का काम पूरा कर लिया है। निवेश आकर्षित करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। केन्द्रीय बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। यह सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। जिस प्रकार मध्यप्रदेश में तेजी से शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है, नया बजट युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए व्यापक अवसर लेकर आया है। शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति का गठन और 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों एवं 500 महाविद्यालयों में एपीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। पर्यटन क्षेत्र में आईआईएम के सहयोग से 10 हजार गाइड्स के कौशल उन्नयन और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से अगले दशक में खेलों के परिदृश्य में बदलाव लाने का लक्ष्य युवाओं को नई दिशा देगा। महिलाओं के लिये एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन लाभदायी होगा। युवा भारत के लिये सेवा क्षेत्र का विस्तार संभावनाओं के नये द्वार खोलेगा और रोजगार और उद्यम के अवसर बढ़ेंगे। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी योजना में महिला उद्यमियों को क्रेडिट लिंक आजीविका से उद्यम स्वामित्व से जोड़ने में मदद मिलेगी। मध्यप्रदेश ने पहले ही इस दिशा में ठोस प्रयास किये हैं।

सिटी ईकॉनामिक रीजन बनाने की नीति मध्यप्रदेश के शहरी विकास के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। शहरों को संगठित आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करने में यह सहायक सिद्ध होगी। शहरी क्षेत्रों में नियोजित आर्थिक विकास, औद्योगिकव्यावसायिक क्लस्टरिंग और आधुनिक अधोसंरचना का निर्माण होगा। इससे मध्यप्रदेश के प्रमुख शहर संगठित आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित होंगे और निवेशअनुकूल शहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। यह निवेश मॉडल मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स तथा व्यापारिक सुगमता को व्यापक रूप से मजबूत बनायेगा।

बजट में सामाजिक समावेश पर पूरा ध्यान दिया गया है। आर्थिक विकास की ये पहल मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। समावेशी विकास के साथ मानव-पूंजी निर्माण को भी मजबूती मिलेगी। शी-मार्ट्स, दिव्यांगजन कौशल योजना, सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और शिक्षाकौशल आधारित पहल से सामाजिक सशक्तिकरण के साथ आर्थिक विकास को समावेशी स्वरूप मिलेगा। इससे मध्यप्रदेश में गुणवत्तापूर्ण मानवपूंजी का सृजन होगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को विकास के केन्द्र में रखते हुए यह बजट प्रशासनिक सरलीकरण, निवेश-अनुकूल नीतियों, संरचनात्मक सुधारों और वित्तीय स्थिरता के माध्यम से मध्यप्रदेश को तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने की ठोस आधारशिला रखता है। मध्यप्रदेश के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 केवल एक नीति-दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का एक ऐतिहासिक अवसर है, जो मध्यप्रदेश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में अत्यंत सहायक एवं परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी।

रिश्ते, शर्तें और डर से घिरी एक पीढ़ी

-प्रियंका सौरभ

आज के समय में यदि कोई सबसे जोखिम भरा सामाजिक कार्य है, तो वह है–किसी को रिश्ते की बात कहना। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि हमारे बदलते सामाजिक मानस की सच्चाई है। जिस विषय को कभी परिवार, भरोसे और सामूहिक निर्णय का आधार माना जाता था, वह आज शर्तों, अपेक्षाओं और भय की प्रयोगशाला बन चुका है। परिणाम यह है कि अच्छे-खासे घरों में पढ़े-लिखे, सक्षम युवा कुंवारे बैठे-बैठे अधेड़ हो रहे हैं, लेकिन समझौते को कमजोरी मानकर ठुकराया जा रहा है।

आज रिश्ते भावनात्मक समझ से अधिक तकनीकी परियोजना की तरह देखे जा रहे हैं। हर प्रस्ताव एक लंबी चेकलिस्ट के साथ आता है–हाइट कितनी है, रंग कैसा है, पैकेज कितना है, घर कितना बड़ा है, जमीन कितनी है, माता-पिता कितने हस्तक्षेप करते हैं, भविष्य में कौन कितना एडजस्ट करेगा। इस गणित में मनुष्य गायब है, आंकड़े उपस्थित हैं। यही वजह है कि रिश्ता तय करने में महीनों लगते हैं, पर टूटने में कुछ हफ्ते भी पर्याप्त हो जाते हैं। यह पीढ़ी सुविधाओं की भाषा में रिश्ते तलाश रही है। लड़कियों को ऐसा घर चाहिए जहाँ घरेलू श्रम की कोई अपेक्षा न हो, जहाँ जिम्मेदारी का बोझ पुरानी सोच मान लिया जाए। वहीं लड़कों को ऐसी बहू चाहिए जो आधुनिक भी हो और परंपरागत अपेक्षाओं का निर्वाह भी बिना सवाल किए करे। दोनों पक्ष चाहते हैं कि सामने वाला समझौता करे, पर स्वयं झुकने को कोई तैयार नहीं। रिश्ते साझेदारी नहीं, सेवाओं की सूची बनते जा रहे हैं।

हनीमून पेरिस में मनाने का सपना है, लेकिन अपने ही देश और अपने परिवेश की जिम्मेदारियों से बचने में पसीना छूट जाता है। यह विरोधाभास केवल भौगोलिक नहीं, मानसिक है। वैश्विक आकांक्षाएँ हैं, पर स्थानीय दायित्वों से परहेज। आधुनिकता का अर्थ सुविधाओं का उपभोग समझ लिया गया है, दायित्वों को स्वीकार करना नहीं।

खेती किसी को करनी नहीं, पर जमीन–कि ल्ले–जरूर होने चाहिए। मेहनत का सम्मान घटा है, संपत्ति का आकर्षण बढ़ा है। जिस समाज की जड़ें श्रम में थीं, वहाँ अब श्रम से दूरी और संपत्ति से निकटता प्रतिष्ठा का मानक बन गई है। रिश्ता तय करते समय परिश्रम, धैर्य, संघर्ष और जीवन-कौशल की जगह संपत्ति, पद और प्रोफाइल ने ले ली है। इंसान का मूल्यांकन उसके चरित्र से नहीं, उसके संसाधनों से किया जा रहा है। आज एक-एक इंच हाइट नापी जाती है; रंग, जाति, सैलरी, कार और सोशल मीडिया की मौजूदगी तक गिनी जाती है। विवाह-पूर्व जाँच एजेंसियों की तरह रिश्तों की पड़ताल होती है। लेकिन तमाम जाँच-पड़ताल के बावजूद छह महीने बाद वही लोग कोर्ट के बाहर खड़े मिल जाते हैं। सवाल यह नहीं कि तलाक क्यों बढ़ रहे हैं; सवाल यह है कि इतनी सावधानी के बाद भी रिश्ते टिक क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमने मानवीय गुणों को मापना छोड़ दिया है–संवाद, सहनशीलता, धैर्य, असहमति में सम्मान और संकट में साथ निभाने की क्षमता। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे त्रासद स्थिति माँ-बाप की है। वे बच्चों से डरते हैं–कि कहीं कुछ कह न दें, कहीं दबाव न डाल दें, कहीं इमोशनल ब्लैकमेलह्व का आरोप न लग जाए। दूसरी ओर बच्चे शादी से डरते हैं–जिम्मेदारी, स्थायित्व और समझौते से। रिश्ता दोनों के बीच पिस रहा है। यह डर का ऐसा चक्र है जिसमें कोई नेतृत्व नहीं चाहता, सब दर्शक बने रहना चाहते हैं। माता-पिता आज निर्णयकर्ता नहीं, केवल वित्तीय और भावनात्मक सहायक बनकर रह गए हैं। वे न रिश्ता सुझा सकते हैं, न आपत्ति जता सकते हैं। वहीं युवा पीढ़ी स्वतंत्रता चाहती है, लेकिन निर्णयों की जवाबदेही से बचना चाहती है। यह असंतुलन रिश्तों को खोखला कर रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने की क्षमता होना चाहिए–यह बुनियादी समझ कहीं खो गई है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि हमारे माँ-बाप का समय अलग था। यह सच है कि तब दुनिया सरल थी, विकल्प कम थे। लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि तब भरोसा था। उन्होंने न काला देखा, न गोरा; न लंबी सूची बनाई, न परफेक्ट प्रोफाइल ढूँढी। बुजुर्गों पर भरोसा किया, परिवार की सामूहिक बुद्धि पर विश्वास रखा और उसी भरोसे के सहारे जीवन जिया। यह नहीं कि तब समस्याएँ नहीं थीं, पर समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति नहीं थी। आज समस्याएँ कम नहीं हुईं, बल्कि समाधान से भागने की आदत बढ़ी है। छोटी-छोटी असहमति को ह्लटॉक्सिकह्व करार देकर रिश्ता तोड़ देना साहस नहीं, पलायन है। विवाह को आजादी का अंत समझा जाने लगा है, जबकि सच यह है कि सही साझेदारी ही व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता देती है। अकेले रहने का विकल्प सबके लिए संभव नहीं, और सबके लिए समाधान भी नहीं। सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल ऐप्स ने अपेक्षाओं को बाजार बना दिया है। हर प्रोफाइल तुलना का विषय है, हर विकल्प अस्थायी। बेहतर की खोज अंतहीन है, इसलिए पर्याप्त कभी मिलता ही नहीं। यह उपभोक्तावादी दृष्टि रिश्तों को भी उपभोग की वस्तु में बदल रही है–पसंद न आए तो बदल दो। लेकिन विवाह मोबाइल फोन नहीं, जिसे हर साल अपग्रेड किया जाए; यह एक दीर्घकालिक सामाजिक अनुबंध है, जिसे निभाने की मानसिकता चाहिए। आज शादी से ज्यादा डर फँस जाने का है। यह डर बताता है कि हमने रिश्ते को सुरक्षा नहीं, बंधन के रूप में देखना शुरू कर दिया है। जबकि सच यह है कि रिश्ता बंधन नहीं, साझी ज़िम्मेदारी है–जहाँ दोनों को देना भी होता है और लेना भी। जहाँ बराबरी का अर्थ समानता नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान होता है। समाधान क्या है? पहला–अपेक्षाओं की ईमानदार समीक्षा। क्या हम जो चाहते हैं, वह हम स्वयं देने में सक्षम हैं? दूसरा–संवाद की बहाली। संवाद केवल बोलना नहीं, सुनना भी है। शादी से पहले ही नहीं, बाद में भी संवाद रिश्ते की रीढ़ है। तीसरा–परिवार की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन। माता-पिता को दखल के खांचे से बाहर निकालकर मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना होगा। चौथा–स्थानीय जीवन के सम्मान की वापसी। पेरिस का सपना बुरा नहीं, लेकिन अपने शहर, अपने काम और अपनी मिट्टी से शर्मिंदा होना आत्मघाती है। यह पीढ़ी प्रतिभाशाली है, शिक्षित है, संभावनाओं से भरी है। इसमें दुनिया बदलने की क्षमता है। पर यदि रिश्तों में साहस नहीं होगा–समझौता करने का साहस, टिके रहने का साहस, साथ सीखने का साहस–तो भविष्य अनिश्चित रहेगा। शादी कोई परीक्षा नहीं, जिसमें शत-प्रतिशत अंक चाहिए हों; यह एक यात्रा है, जिसमें गिरते-पड़ते, सीखते हुए आगे बढ़ना होता है।

केंद्रीय बजट 2026-2027

(पवन वर्मा-विनायक फीचर्स)

मध्यप्रदेश की राजनीति लंबे समय से केंद्र से क्या मिला के सवाल में उलझी रही है, लेकिन बजट 2026-27 ने बहस की दिशा ही बदल दी है। अब मुद्दा हिस्सेदारी का नहीं, भूमिका का है। सवाल यह नहीं है कि राज्य को कितना पैसा मिला, बल्कि यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय विकास रणनीति में मध्यप्रदेश को किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बजट में मध्यप्रदेश को मांगने वाले राज्य की तरह नहीं, बल्कि शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के प्रयोग स्थल की तरह देखा गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लिए यह बजट साधारण आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि डबल इंजन सरकार की राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा है। टियर-2 और टियर-3 शहरों को सिटी इकॉनमिक रीजन बनाना, राजधानी भोपाल को यूनिवर्सिटी टाउनशिप और मेट्रो विस्तार से जोड़ना, जिलों में स्वास्थ्य और महिला केंद्रित ढांचे को मजबूत करना,ये सभी फैसले संकेत दे रहे हैं कि अब केंद्र और राज्य का तालमेल नारों में नहीं, शहरों की बनावट और जमीनी फैसलों में दिखाने की कोशिश हो रही है। मध्यप्रदेश इस बजट में पहली बार उपेक्षा की शिकायत करता राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास एजेंडे का सक्रिय मोहरा बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में मध्यप्रदेश सरकार, यह संयोग नहीं, बल्कि नीति और नीयत का ऐसा मेल है, जिसमें विकास को जमीन पर उतारने की स्पष्ट मंशा दिखाई देती है। बजट 2026-27 को मध्यप्रदेश और उसके शहरों के संदर्भ में देखा जाए, तो यह साफ होता है कि केंद्र और राज्य के बीच डबल इंजन की अवधारणा अब केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहरी विकास, निवेश और आर्थिक विस्तार की ठोस रणनीति में बदल चुकी है। यह बजट संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश की पहचान केवल कृषि प्रधान राज्य के रूप में नहीं, बल्कि तेजी से उभरते शहरी और आर्थिक केंद्रों के राज्य के रूप में स्थापित की जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहर इस रणनीति के केंद्र में हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, तकनीक और रोजगार एक साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यभार संभालने के बाद जिस ह्यनिवेश, नवाचार और नगरीय विकास की बात कही थी, बजट 2026-27 उस सोच को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन देता नजर आता है। भारत के विकास मॉडल में लंबे समय तक शहरों को केवल प्रशासनिक या जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों के रूप में देखा गया लेकिन बजट 2026-27 से अब शहरों को विकास की धुरी के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

सिटी इकॉनमिक रीजन की अवधारणा इस बदलाव का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। इसके तहत भोपाल जैसे शहरों को केंद्र में रखकर आसपास के औद्योगिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को एक साझा आर्थिक इकाई में बदला जाएगा। यह मॉडल मध्यप्रदेश को केवल उपभोक्ता राज्य नहीं, बल्कि उत्पादन और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। इंदौर, जो पहले ही व्यापार और स्टार्टअप संस्कृति के लिए जाना जाता है, इस ढांचे में राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू सकता है। वहीं भोपाल जैसे शहर प्रशासनिक राजधानी से आगे बढ़कर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभर सकते हैं। शहरी आत्मनिर्भरता की मजबूत बुनियाद बनाने की दिशा में बजट 2026-27 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है नगरीय निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन। यह व्यवस्था शहरी विकास को अनुदान आधारित मॉडल से आत्मनिर्भर मॉडल की ओर ले जाती है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे नगर निगम अब केवल सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी योजनाओं और विश्वसनीयता के बल पर पूंजी बाजार से संसाधन जुटा सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा बड़े बॉन्ड इश्यू पर प्रोत्साहन देना यह दशार्ता है कि शहरी विकास में अब पारदर्शिता और पेशेवर प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। यह बदलाव नगर निगमों की कार्यसंस्कृति में भी सुधार ला सकता है और विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने में मददगार साबित होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा केंद्रीय स्थान मिला है। बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय पर दिया गया जोर इसी नीति की निरंतरता है। इसका सीधा लाभ मध्यप्रदेश के शहरों को मिलने वाला है। बेहतर सड़कें, मेट्रो परियोजनाएं, जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी आवास। ये सभी पहलू शहरों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ-साथ निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करते हैं। भोपाल-इंदौर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि पूरे शहरी परिदृश्य को नया आकार देने वाले साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की रीढ़ बताने की सोच, इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकती है। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग पर दिया गया जोर मध्यप्रदेश के लिए दूरगामी असर वाला है। विशेष रूप से भोपाल जैसे शहर, जहां उच्च शिक्षा और मानव संसाधन की मजबूत उपस्थिति है, इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर और तकनीक आधारित उद्योगों के विस्तार से भोपाल की पहचान केवल प्रशासनिक केंद्र तक सीमित नहीं रहेगी। यह शहर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और नवाचार का केंद्र बन सकता है, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। मध्यप्रदेश की ताकत उसकी कृषि है और बजट 2026-27 इस ताकत को शहरी अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाता है। तकनीक आधारित कृषि, रिसर्च और वैल्यू एडिशन पर जोर देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि किसान और शहर दोनों एक-दूसरे से लाभान्वित हों। शहरों के आसपास एग्री-प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच मजबूत सेतु का काम करेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा। बजट 2026-27 में यह स्पष्ट झलक मिलती है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शहरी विकास को नई दिशा देना चाहती हैं,इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय विकास दृष्टि और मुख्यमंत्री मोहन यादव की राज्य केंद्रित प्राथमिकताएं जब एक साथ आगे बढ़ेगीं , तो उसका असर नीति से लेकर जमीन तक दिखाई देगा ।

पुणे में यादव परिवार महोत्सव का भव्य आयोजन, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एकजुटता का संदेश

पुणे (उत्तरशक्ति)। श्री कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में यादव समाज का यादव परिवार महोत्सव पुणे के धानोरी स्थित अम्बेडकर भवन में अत्यंत हर्षोल्लास और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ, युवा, महिला-पुरुषों की बड़ी संख्या में सहभागिता देखने को मिली। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में नगरसेविका श्रीमती रेखाताई चन्द्रकांत टिगरे उपस्थित रहीं। उनके साथ सत्यनारायण यादव (संपादक-यदु यादव कोष, मुंबई), श्रीमती माला यादव (नागपुर), एडवोकेट जयराम यादव (ठाणे), राम प्रकाश यादव, कैप्टन मान सिंह यादव, सुनील यादव (प्रो. लक्ष्मी फरसाण, मुंबई), आचार्य सूरजपाल यादव (भिवंडी) आदि जैसे प्रतिष्ठित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का मार्गदर्शन उद्योगपति सुनील यादव ने किया, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फिजूलखर्ची वाली शादियों से बचते हुए सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक और व्यावहारिक उपाय अपनाना समय की आवश्यकता है। इससे न केवल आर्थिक बोझ कम होगा बल्कि सामाजिक समरसता भी मजबूत होगी। आयोजक मंडल की ओर से सुदर्शन सिंह यादव (अध्यक्ष), राधेश्याम यादव (उपाध्यक्ष), सियाराम यादव (महासचिव) और दल सिंगार यादव (कार्याध्यक्ष) ने ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य वैवाहिक जोड़े मिलाकर समाज के जरूरतमंद परिवारों का विवाह संपन्न कराना, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। वक्ताओं ने एक स्वर में समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने, कुरीतियों को त्यागने और नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में समाजसेवियों और अतिथियों का सम्मान किया गया। यादव परिवार महोत्सव ने पुणे में न केवल सामाजिक चेतना को नई दिशा दी, बल्कि सामूहिक प्रयासों से समाज सुधार का सशक्त संदेश भी दिया।

गौ सेवा के साथ मनाया गया पियुष धोडी का जन्मदिन

पालघर(उत्तरशक्ति)। समाज सेवा की भावना को साकार रूप देते हुए पियुष धोडी ने अपना जन्मदिन एक अनोखे और प्रेरणादायक तरीके से मनाया। 27 जनवरी को अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने गौ सेवा और अनाथ बच्चों की सेवा कर यह संदेश दिया कि सच्ची खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। इस अवसर पर एक गौशाला में मौजूद 230 से अधिक गाय, बैल और बछड़ों को चारा एवं फल खिलाए गए। गौ माता की सेवा करते हुए पियुष धोडी ने कहा कि ङ्गगौ सेवा केवल धर्म नहीं, बल्कि मानवता का कर्तव्य है ख्र साथ ही, जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक छोटा सा सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें अनाथ बच्चों को भोजन कराया गया तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएँ वितरित की गईं। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखते ही बनती थी। उनका सामाजिक संदेश ङ्ग प्रत्येक के साथ, प्रत्येक के लिए युवाओं के लिए प्रेरणा बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पियुष धोडी के इस कार्य की सराहना की है।

मूलभूत सुविधाओं के लिए 10 लाख रुपये तक अनुदान

◆20 फरवरी तक आवेदन जमा करने की अपील

पालघर(उत्तरशक्ति)। बौद्ध समाज के सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक की अनुदान योजना लागू की जा रही है।

महाराष्ट्र शासन के अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा 7 अक्टूबर 2024 को जारी शासन निर्णय के अनुसार, राज्य के धमार्दाय आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत वे संस्थाएं, जिनमें 51 प्रतिशत से अधिक विश्वस्त अथवा सदस्य बौद्ध समाज से संबंधित हैं, इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। यह योजना बौद्ध समाज की सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु 27 जनवरी 2026 को परिपत्र जारी किया गया है। पात्र संस्थाओं को शासन निर्णय में निर्धारित प्रारूप के अनुसार आधारभूत सुविधाओं से संबंधित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने जिले की पात्र एवं इच्छुक संस्थाओं से अपील की है कि वे अपने प्रस्ताव जिला नियोजन अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, पालघर के कार्यालय में 20 फरवरी 2026 को सायं 5.00 बजे तक जमा करें।

पालघर जिला परिषद द्वारा आयोजित अधिकारी व कर्मचारी खेल प्रतियोगिता संपन्न

पालघर(उत्तरशक्ति)। जिला परिषद पालघर द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गई। विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए दहानू तहसील ने लगातार चौथी बार सम्मान कप जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।

इस उल्लेखनीय सफलता में महिला खिलाड़ियों का योगदान विशेष रूप से सराहनीय रहा। 31 जनवरी से प्रारंभ हुई इन खेल प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह सोमवार 2 फरवरी 2026 को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज अहमद शरीकमसलत, मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी सचिन कवठे, जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) व्यंकटराव हुंडेकर, सभी विभाग प्रमुख तथा समूह विकास अधिकारी उपस्थित थे।

इन प्रतियोगिताओं में जिला परिषद मुख्यालय सहित जिले के सभी आठ तहसीलों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में खो-खो, कबड्डी, क्रिकेट, गोला फेंक, थाली फेंक, म्यूजिकल चेयर, कैरम, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, दौड़, रिले और रंगोली जैसे विविध खेल शामिल थे। तीन दिनों तक चली इन प्रतियोगिताओं से कर्मचारियों में खेल भावना, टीमवर्क व सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। इस आयोजन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने खिलाड़ियों के किट (शर्ट व ट्राउजर) का प्रायोजन किया। साथ ही प्रतियोगिताओं का लाइव टेलीकास्ट भी बैंक द्वारा किया गया, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने प्रतियोगिताओं के सफल, अनुशासित एवं आनंददायक आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी तथा भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने खेल मैदान उपलब्ध कराने के लिए सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय का आभार व्यक्त किया और एक ही स्थान पर सभी खेलों के आयोजन से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की बात कही। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे ने भी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक भावना को बढ़ावा देने वाले ऐसे कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक हैं।

सभी विजेता खिलाड़ियों एवं टीमों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र व पदक देकर कर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे द्वारा प्रत्येक को 1000 रुपये नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रतियोगिता के सफल आयोजन में योगदान देने वाली आयोजन समिति के सदस्य, निर्णायक (अंपायर) तथा सफाई कर्मचारियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

दहानू तहसील ने लगातार चौथी बार सम्मान कप पर कब्जा जमाया

मुंबई महानगरपालिका की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद, आज जलापूर्ति रहेगी बंद

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। मुंबई शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली तानसा पाइपलाइन भिवंडी शहर के टेमघर गोविंद नगर क्षेत्र में फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया है। इस घटना के कारण भिवंडी शहर के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार (3 तारीख) को जलापूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर ने दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंबई पाइपलाइन के समीप ताडाली से टेमघर मार्ग पर सड़क का कंक्रीटीकरण तथा एक छोटे पुल का निर्माण कार्य जारी है। इसके साथ ही वहां सुरक्षात्मक दीवार बनाने का काम भी चल रहा है। खुदाई के दौरान पोकलेन मशीन की चपेट में आने से पाइपलाइन फट गई, जिससे लाखों लीटर पानी बह गया। इस पाइपलाइन के माध्यम से भिवंडी शहर को प्रतिदिन लगभग 35 एमएलटी पानी की आपूर्ति होती है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण मुंबई

शहर के साथ-साथ भिवंडी शहर की जलापूर्ति पर भी असर पड़ेगा। इसके चलते कामतघर, ताडाली, पद्मानगर, मानसरोवर, धोबी तलाव, सौदागर मोहल्ला, बाजारपेठ, ठाणे रोड सहित शहर के अधिकांश इलाकों में पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई महानगरपालिका के जलापूर्ति विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। क्षेत्र में जमा पानी को निकाला जा रहा है तथा पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। उक्त जानकारी भिवंडी मनपा के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर ने दी है।

जरूरतमंदों को कम्बल, साड़ी एवं फल भेंट कर मनाया पत्रकार संघ अध्यक्ष रामप्रकाश निराला का जन्मदिन

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध पत्रकारों के संगठन बोईसर-पालघर पत्रकार संघ(रजि.) की ओर से विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी रविवार 01फरवरी 2026 को पत्रकार संघ के अध्यक्ष एवं लोकप्रिय हिंदी पाक्षिक बोईसर समाचार के प्रधान सम्पादक रामप्रकाश निराला का 65 वां जन्मदिन समाजसेवा दिवस के तौर पर मनाया गया। जन्मदिन कार्यक्रम की शुरूआत बोईसर (चित्रालय) स्थित सम्राट होटल में मान्यवरों की प्रमुख उपस्थिति में केक काट कर की गई। इसके बाद सभी उपस्थितजनों ने सुप्रसिद्ध समाजसेवी व बोईसर-पालघर पत्रकार संघ(रजि.) के अध्यक्ष रामप्रकाश निराला को पुष्पगुच्छ व उपहार देकर जन्मदिन की

बधाई एवं शुभकामनायें दी। तत्पश्चात पत्रकार व समाजसेवी लोगों की टीम श्री संतोषी माता मंदिर, आशागढ़ व श्री महालक्ष्मीमाता मंदिर विवलवेढे (दहानू) पहुंचकर मन्दिर परिसर में बैठे जरूरतमंदों को फल-फ्रूट, नास्ता, कम्बल भेंट देने के साथ ही साथ जरूरतमंद महिलाओं को साड़िया भी दी गयी। उपरोक्त भेंटवस्तु पाकर इन जरुरतमन्दो ने पत्रकार निराला को जन्मदिन पर उनकी लम्बी आयु की कामना की। इस अवसर पर बोईसर- पालघर पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष भूपनारायण शुक्ला, प्रवीण पाटील व निलेश नगरकर, महासचिव मोहन म्हात्रे, सचिव दीपक निराला, कोषाध्यक्ष नीता राऊत, कार्यकारिणी सदस्य मृत्युंजय पाण्डेय व संगीता शाह , मंगेश नगरकर, बजरंग दल के प्रवक्ता मनोज मिश्रा, समाजसेवियों में एस एस तिवारी, पुष्पा तिवारी, सुनीता सकपाल, अरविंद शाह, शीला करोतिया आदि उपस्थित थे। वरिष्ठ पत्रकार रामप्रकाश निराला को जन्मदिन की बधाई देने वाले अन्य मान्यवरों में राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ललित माली व रोहित सिंह, समाजसेवी शिवाजी रेंबालकर, अनंत दलवी, वरिष्ठ पत्रकार जयवंत आहिरे, प्रोटेक कंप्यूटर एवं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सेंटर के संचालक सचिन जाधव व पायल जाधव, गंगवाल हेल्थ केयर कम्पनी के प्रबंधक अनिल जगदाले महेश संखे, परशुराम पाटील, पत्रकार अमित निगम, अखिलेश चौबे, पंकज गुप्ता व पराग यादव सहित अनेक राजनेता, पत्रकार एवं समाजसेवियो ने पत्रकार निराला को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

विधायक दिलीप लांडे ने चांदीवली में श्री विश्वकर्मा भवन का किया लोकार्पण

मुंबई (उत्तरशक्ति)। चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के माध्यम से समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। विधायक दिलीप लांडे ने अपने टछअ फंड से चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में हर जगह सोशल वेलफेयर सेंटर बनवाने का काम किया है। हाल ही में बने श्री विश्वकर्मा भवन का उद्घाटन किया गया है। चांदीवली इलाके में विश्वकर्मा समाज के जरिए दिलीप लांडे से सोशल वेलफेयर सेंटर बनवाने की मांग की गई थी। इस मांग पर ध्यान देते हुए लांडे ने अपने फंड से असल्फा हिमालय सोसाइटी में श्री विश्वकर्मा समाज सेवा समिति का सोशल

लोकार्पण कार्यक्रम मे समाज के सदस्य हुए उपस्थित

वेलफेयर सेंटर बनवाया। श्री विश्वकर्मा समाज सेवा समिति का सोशल वेलफेयर सेंटर बनाने का काम MLA दिलीप मामा लांडे की लगातार कोशिशों से हुआ है। इस श्री विश्वकर्मा सोशल वेलफेयर सेंटर का उद्घाटन समारोह टछअ दिलीप मामा लांडे ने किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 164 के पार्षद हरीश भारदिगे, शाखाप्रमुख मंगेश सकपाल, कमल जोशी, पप्पू विश्वकर्मा समेत बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के सदस्य मौजूद थे।

हाफिज जी ग्रुप व यूके ग्रुप द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन में 10 जोड़े बंधे वैवाहिक बंधन में

आचार्य सूरजपाल यादव

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। समाज में भाईचारे और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूती देने के उद्देश्य से हाफिज जी ग्रुप एवं यूके ग्रुप की ओर से शनिवार को हफीज मैरिज हॉल में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 10 जोड़ों का निकाह/विवाह सादगीपूर्ण माहौल में विधि-विधान के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में भिवंडी पूर्व के विधायक रईस काशम शेख सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और परिजन मौजूद रहे। आयोजकों की ओर से नवविवाहित जोड़ों को घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्री और उपहार भेंट कर उनके सुखमय दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दी गईं। आयोजन स्थल पर अनुशासन और सादगी के साथ उत्साह का माहौल देखने को मिला। हाफिज जी ग्रुप के संस्थापक हाफिज अकरम खान और यूके ग्रुप के संस्थापक सलाम भाई ने मंच से सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने कहा कि

सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिलती है और समाज में एकता व सहयोग की भावना मजबूत होती है। उन्होंने आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्य लगातार जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम के समापन पर नवविवाहित जोड़ों, बरातियों और घरातियों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इस सामाजिक पहल की शहर में व्यापक सराहना की जा रही है।

भाजपा उत्तर मुंबई द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में बजट को विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करनेवाला बताया

मुंबई (उत्तरशक्ति)। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई प्रसिद्धि विभाग द्वारा आज केंद्रीय अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय अर्थ संकल्प 2026 के संदर्भ में पत्रकार परिषद लोक कल्याण कार्यालय कांदिवली पश्चिम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ,विधायक अतुल भातखलकर , वि.योगेश सागर ,वि.मनीषा चौधरी,वि.संजय उपाध्याय, कार्यक्रम प्रमुख निखिल व्यास, महामंत्री बाबा सिंह, अप्पा बेलवलकर एवं उत्तर मुंबई ज़िला के पदाधिकारी गण उपस्थित थे।विधायक अतुल भातखलकर ने संपूर्ण अर्थ संकल्प का ब्यौरा दिया और सर्व समावेशक, विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिए। 2026 के केंद्रीय बजट में ऐसी अनेक योजनाओं को लागू किया जा रहा है जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश गतिमान होगा। स्थानिक स्वराज्य संस्था को मजबूत करने की दिशा में

100 करोड़ की राशि का प्रावधान कर देश की स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य इस बजट के द्वारा सोचा गया है। जिसका लाभ महाराष्ट्र राज्य मुंबई महानगरपालिका एवं पंचायतों को होगा। परिवार में पति पत्नी दोनों काम काजी है वहां 24 लाख तक की कर मुक्ति लागू की गई है जो अपने आप में बड़ा निर्णय है।सर्वसामान्य व्यक्ति को दिलासा देनेवाला यह बजट है ऐसा भी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा।रोजगार उपलब्धि के लिए एमएसएमई ग्रोथ फंड को बढ़ावा देने के कारण इस बजट से रोजगार उपलब्धि मजबूत होगी। ऐसे अनेक विषयों पर प्रकाश डालते हुए अतुल भातखलकर ने यह भी कहा कि विकास की रफ्तार को तेज करने वाला यह बजट राजकोषीय अनुशासन के साथ विकसित भारत 2047 के स्वप्न पूर्ति का बजट है। इस पत्रकार परिषद में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातखलकर, मनीषा चौधरी, योगेश सागर, संजय उपाध्याय, निखिल व्यास, बाबा सिंह, रश्मिकांत बेलवलकर प्रसिद्धि प्रमुख नीला कनुभाई राठोड़ सोनी और अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे।

अजीत पवार की मौत 'हादसा नहीं साजिश' : संजय राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत पर सवाल उठाते हुए विमान दुर्घटना में साजिश की आशंका जताई। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो विरोधी गुटों के बीच संभावित सुलह की अटकलें तेज हैं। राउत ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित एनसीपी विलय का समर्थन करने के बाद अजीत पवार पर दबाव डाला गया और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सिंचाई घोटाले की फाइलों का इस्तेमाल उन्हें धमकाने के लिए किया। राउत के अनुसार, इस घटना के कुछ ही दिनों के भीतर अजीत पवार की अचानक मौत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अजीत दादा की दुर्घटना पर सवाल जरूर उठेंगे... सवाल उठने ही चाहिए। जिस तरह से अजीत पवार जैसे नेता... महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं - इसकी जांच होनी चाहिए... मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आगे कहा, पर्दे के पीछे कुछ जरूर हुआ है... उनकी रहस्यमय तरीके से 10 दिनों के भीतर मृत्यु हो गई। इससे हम क्या समझते हैं? यह हमें न्यायमूर्ति लोया की याद दिलाता है।

इससे पहले, एनसीपी नेता अमोल मितकारी ने भी इसी तरह के संदेह व्यक्त किए थे, जिसमें उन्होंने अचानक पायलट परिवर्तन, विमान के मार्ग में बदलाव और दुर्घटनास्थल से बरामद शवों की स्थिति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, एक भी कागज नहीं जला, लेकिन शव जले हुए थे। इससे संदेह पैदा होता है। मितकारी ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच शुरू करने का आग्रह किया है और उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप की भी मांग करेंगे। राजनीतिक तूफान के बावजूद, एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने सभी से इस त्रासदी का राजनीतिकरण न करने की अपील की और जोर देकर कहा कि यह दुर्घटना एक हादसा थी।

व्हील ऑफ फॉर्च्यून पर यह खुशी भरा डांस मोमेंट लोगों का दिल जीत रहा है

मुंबई/पटना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लेटेस्ट प्रोमो में एक और यादगार पल देखने को मिला, जब अक्षय कुमार ने कंटेस्टेंट नरेश के बारे में अपनी बात से दर्शकों को खूब हंसाया, उन्हें एक्टर अवतार गिल का हमशक्ल बताया। मजे को और बढ़ाते हुए अक्षय ने मजाक में नरेश को सबसे कूल मैथ्स टीचर बताया, जिसने तुरंत दर्शकों का दिल जीत लिया। यह हल्की-फुल्की बातचीत जल्द ही एक सेलिब्रेशन के पल में बदल गई जब अक्षय कुमार ने नरेश और उनकी पत्नी को स्टेज पर अपने साथ आने के लिए बुलाया।

इसके बाद एक खुशी भरा डांस सीक्वेंस हुआ, जिसमें अक्षय ने कपल के साथ हिट ट्रैक तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया पर डांस किया। इस अचानक हुए परफॉर्मेंस से सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और शो की गर्मजोशी भरी, पारिवारिक भावना देखने को मिली। नरेश के मिलनसार स्वभाव और उनकी पत्नी के उत्साह ने इस पल को और भी खास बना दिया, जबकि अक्षय की एनर्जी और हौसला-अफजाई ने माहौल को और भी शानदार बना दिया।

उत्तरशक्ति

* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामी: शरद फागुराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल स्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालय: मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

साइबर क्राइम सेल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से 111 गुमशुदा मोबाइल बरामद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। साइबर क्राइम सेल/थाना जनपद जौनपुर व थानो की साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से 111 गुमशुदा मोबाइल (कीमत करीब बीस लाख रुपए) अब तक कुल 1130 मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को किया गया सुपुर्द। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना जनपद जौनपुर द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से 111 गुमशुदा मोबाइल (कीमत करीब बीस लाख रुपए) को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया गया। जनपद में अब तक कुल 1130 मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया जा चुका है। गुमशुदा मोबाइलों के प्रार्थना पत्रों/ सीईआईआर पोर्टल के आधार पर साइबर क्राइम थाना जनपद जौनपुर पुलिस टीम द्वारा पीड़ितों के गुम हुए 111 मोबाइलो में जनपद के भिन्न-भिन्न थाना क्षेत्र से व थानो के साइबर सेल (थाना शाहगंज 19 मोबाइल, खुटहन 04, कोतवाली 03, लाइनबाजार 03,सरायख्वाजा 03, तेजीबाजार 02, सरपतहाँ 03, सुजानगंज 03, मडियाहू 03, मुगराबादशाहपुर 02, नेवढिया 01) द्वारा बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद आजमगढ, प्रयागराज, बहराईच, लखनऊ, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, बलिया, भदोही से मोबाईल फोन बरामद किया गया। कुछ मोबाईल फोन अन्य प्रान्त (जैसे-दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखण्ड, बिहार, राजस्थान) से बरामद किया गया। बरामद मोबाइलों में मुख्यतः वन प्लस, वीवो, रेडमी, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, पोको, नोकिया व सैमसंग कम्पनी की मोबाइल है, जिनका बाजार मूल्य लगभग बीस लाख रुपये है।

बरामद मोबाइल को अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव नोडल साइबर क्राइम व देवेश सिंह क्षेत्राधिकारी सदर/ साइबर क्राइम द्वारा मोबाइल स्वामियों को वितरित किया गय । अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बताया गया कि मोबाइल फोन गायब होने की दशा में थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराने के उपरान्त , सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत करें। साइबर अपराध के प्रति जागरुकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल 1930 पर आनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्पडेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें। अपना खोया मोबाइल पाकर सभी मोबाइल धारक काफी सन्तुष्ट व खुश दिखे ।

शिक्षा से ही समग्र समाज का विकास संभव: सैयद कमर हसनैन रिजवी

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शहर के सिपाह स्थित जामिया लिल बनात के कैंपस में एक सेमिनार आयोजित हुआ जिसका उन्वान था नई पीढ़ी उनकी शिक्षा और संस्कार और हमारी जिम्मेदारी जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बैंच के न्यायाधीश सैयद कमर हसनैन रिजवी रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि जौनपुर न्यायालय के एडिशनल सी जे एम मुकीम अहमद और विशिष्ट अतिथि के रूप में जावेद शगिर रहे।

सैयद कमर हसन रिजवी न्यायाधीश हाई कोर्ट इलाहाबाद ने नई पीढ़ी की शिक्षा और संस्कार पर विस्तृत से व्याख्यान किया उन्होंने बताया कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि नए पौधे के रूप में उगने वाली नई पीडिओ को किस तरीके से उनके मस्तिष्क को उस और मोड दिया जाए जिसमें उनकी रुचि ज्यादा हो, अन्यथा रुचि से हटकर दूसरे विषयों पर उनकी शिक्षा को नया आयाम नहीं दिया जा सकता। जावेद शगिर फाउंडर एव मैनेजर शिबली आर सी ए ने बताया कि शिक्षा के लिए लोगों को एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा चंदा देकर हर मोहल्ले और हर कस्बे में नए-नए शिक्षा के केंद्र खोलने होंगे ताकि नई पीढ़ी को सारी सुविधाएं वहां से मिले, डॉक्टर सरफराज खान ने भी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला मौलाना अनवार अहमद कासमी अध्यक्ष एवं फाउंडर ने बताया कि जब आदमी समाज में कुछ नया करना चाहता है तो उसके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं बस एक बार अपने अंदर एक अलख जगा कर निकलना चाहिए कारवां अपने आप बन जाता है । सेमिनार शिक्षा एवं नौजवानों की नई पीढ़ी और हमारी जिम्मेदारी पर अन्य वक्ताओं ने भी व्याख्यान किया कार्यक्रम की अध्यक्षता की एडवोकेट सलमान अहमद खान ने वही संचालन किया अकरम अहमद ने। मुख्य रूप से हुजैफा खान ,अंसार अहमद, रियाजुल हक, डॉ.इम्तियाज अहमद, शब्बीर हैदर अम्मार, शाहनवाज अहमद सभासद, फैसल यासीन पूर्व सभासद आदि मौजूद रहे।

डालिम्स सनबीम स्कूल में भव्य वार्षिक मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। डालिम्स सनबीम स्कूल, जौनपुर के विद्यालय परिसर में कल रात्रि वार्षिक मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह का आयोजन अत्यंत उत्साह और रंगारंग आयोजनों के साथ किया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों, विद्यार्थियों और अतिथियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जिससे यह आयोजन पूरे डालिम्स परिवार के लिए एक यादगार अवसर बन गया।

इस कार्यक्रम की शोभा मुख्य अतिथि डॉ.अब्दुल कादिर खान, अध्यक्ष, मोहम्मद हसन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, विशिष्ट अतिथि जेएमएस ग्रुप के चेयरमैन जितेंद्र यादव, तथा विशेष अतिथि डॉ. कमर अब्बास एवं डॉ. हैदर अब्बास, आर .पी सिंह, की गरिमामयी उपस्थिति से बढ़ी। उनकी उपस्थिति ने समारोह को गरिमा और प्रेरणा प्रदान की।

विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत एवं मंचीय प्रस्तुतियों सहित विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें उनकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और प्रतिभा स्पष्ट रूप से दिखाई दी। सुंदर रूप से सुसज्जित विद्यालय परिसर, रोचक खेलों और उत्सवपूर्ण वातावरण ने संध्या को और भी आकर्षक बना दिया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ.अब्दुल कादिर खान ने विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बच्चों की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए उन्हें बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। साथ ही उन्होंने समग्र शिक्षा के प्रति विद्यालय स्टाफ के समर्पण और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।

विशिष्ट अतिथि, जेएमएस ग्रुप के चेयरमैन ने भी विद्यार्थियों को अनुशासन और मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और विद्यालय द्वारा निर्मित सकारात्मक एवं पोषणकारी शैक्षिक वातावरण की प्रशंसा की।

कार्यक्रम में नवाल अहमद, फातेमातुज्जेहरा, नेदा, सबा वाजिया सहित विद्यालय के अन्य सम्मानित स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे, जिनके सहयोग से कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो सका।

समारोह के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती अलका गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अभिभावकों के निरंतर विश्वास और सहयोग, विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी, अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति तथा शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

यह वार्षिक मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम एक बार फिर डालिम्स सनबीम स्कूल की एकता, रचनात्मकता और उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है।

जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम एवं कृषि विभाग को सभी किसानों की आईडी बनवाने के दिए निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की अगली किश्त पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना की अगली किश्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराया होगा।

किसानों को जागरूक करने के लिए कैंप लगेंगे: उन्होंने जिलाधिकारियों से व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य में तेजी लाने को कहा मुख्य सचिव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण को त्वरित गति से पूरा किया जाए। किसानों को जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएं और रजिस्ट्री टीमों को सक्रिय रखा जाए। पूर्ण पारदर्शिता और सतर्कता बरतते हुए सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र किसान रजिस्ट्री के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे।

लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी: बैठक में बताया गया कि जनपद में पीएम किसान के कुल 879354 लाभार्थियों में से अब तक 537530 (61.13%) किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है शेष किसानों की फार्मर रजिस्ट्री 31 मार्च 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिया गया है। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं उप कृषि निदेशक को पत्र लिखकर प्रति तहसील प्रतिदिन सर्वोच्च प्राथमिकता के दृटिगत 1500 फार्मर रजिस्ट्री बनवाने का निर्देश दीए है ताकि कोई भी पात्र कृषक योजना से वंचित न हो सकें।

बक्शा में कार-बाइक की टक्कर में दो युवक घायल

दानिश सिद्दीकी

बक्शा, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। स्थानीय थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे एन एच 731 पर सवंसा गांव के पास सोमवार सुबह 10:30 बजे एक कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद दोनों घायलों को तत्काल सीएचसी नौपेड़वां भेजा गया। जानकारी के अनुसार, घायल युवकों की पहचान

प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र स्थित महुली गांव निवासी सूरज विश्वकर्मा (पुत्र शिवबली विश्वकर्मा) और विकास सिंह (पुत्र बृज बहादुर सिंह) के रूप में हुई है। वे सोमवार सुबह दवा लेने और अन्य कार्य से जौनपुर शहर जा रहे थे। जैसे ही वे बक्शा थाना क्षेत्र के सवंसा गांव के पास नेशनल हाईवे एन एच 731 पर पहुंचे, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घायलों ने बताया कि कार का नंबर यू पी 62 बी एल 1555 था। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी मिली है और घायलों का इलाज सीएचसी नौपेड़वां में चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

लोजपा (रामविलास) के प्रदेश महासचिव विकास पांडे का जौनपुर आगमन पर कार्यकताओं ने किया स्वागत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रधान प्रदेश महासचिव विकास पांडे के जौनपुर आगमन पर पार्टी कार्यकताओं द्वारा जोरदार एवं भव्य स्वागत किया गया।

रविवार को पार्टी के जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवाहन पर पहुंचे प्रदेश महासचिव ने कार्यकताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में विकास पांडे ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार है और पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रदेश की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है।

प्रदेश महासचिव ने यह भी घोषणा की कि वे स्वयं जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जीत दर्ज करेगी।

विकास पांडे ने पार्टी की जिला अध्यक्ष एडवोकेट रीता सरोज की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जिले में संगठन को काफी मजबूती मिली है और कार्यकताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और पूरे जोश के साथ पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

मछलीशहर क्षेत्राधिकारी प्रतिमा वर्मा ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को दिलाई शपथ, चलाया हस्ताक्षर अभियान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मुंगराबादशाहपुर थाना परिसर में सोमवार को बाल विवाह मुक्त भारत

जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में आएं क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों व छात्र छात्राओं को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता किया गया। इस दौरान सीओ प्रतिमा वर्मा ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को शपथ दिलाई।

सीओ प्रतिमा वर्मा ने लोगों को बाल विवाह की दुष्परिणामों के प्रति आगाह किया। कहा कि कई बार परिवार के अशिक्षित होने के कारण लड़कियां इस पीड़ा की शिकार हो जाती हैं। सामाजिक दबाव के चलते भी परिवार छोटी उम्र में अपनी बेटियों का विवाह कर देते हैं, जो एक अपराध की श्रेणी में आता है।उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन यह तभी लागू हो पाएगा जब सबलोग मिलकर इसे जन अभियान का रूप देंगे। कहा कि अज्ञानता और सामाजिक दबाव के चलते परिवार बाल्यावस्था में ही अपनी बेटियों का विवाह कर देते हैं, जबकि उन्हें यह ज्ञात होता है कि इस उम्र में बालिका ना तो शारीरिक रूप से सक्षम होती है और ना ही जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में होती है।जिला प्रोबेशन विभाग से आए चाइल्ड हेल्पलाइन जिला समन्वयक शिवम कुमार सिंह ने बाल विवाह प्रतिरोध कानून की जानकारी देते हुए बताया कि इसकी शुरूआत अंग्रेजी शासन काल में शारदा एक्ट के रूप में हुई थी।

शिक्षा एक सतत और सर्वांगीण विकास की प्रक्रियाः कृपाशंकर सिंह

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शिक्षा एक सतत और सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है जिसमें कर्म करते रहने से अधिकार स्वतः प्राप्त होते है उक्त बातें पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह ने रामआधार सिंह इंटर कालेज बैजारामपुर के वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए कही। आगे उन्होंने कहाकि यह विद्यालय बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है यही कारण है कि यहां पढ़ रहे बच्चों में प्रत्येक वर्ष कोई न कोई जिला

व प्रदेश लेबल पर टॉप करता है। भाजपा प्रवक्ता ओमप्रकाश सिंह ने कहाकि इस विद्यालय का उद्देश्य छात्र-छात्राओ को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है, तभी विद्यालय के बच्चे हर वर्ष एक विशेष स्थान बनाये रखते हैं। इस मौके पर सत्येन्द्र सिंह फंटू, श्यामराज सिंह, अखिलेश सिंह, धर्मेन्द्र, सत्यम सहित आदि शिक्षक उपस्थित रहे। अतिथियों का आभार प्रबंधक विनोद सिंह ने व्यक्त किया।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्वयंसेवकों ने निकाली जन जागरूकता रैली

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के राजातालाब आराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के जख्खिनी स्थित राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को प्राचार्य प्रो. डॉ. संतोष सिंह के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेवा योजना का द्वितीय एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। जिसके दौरान स्वयंसेवकों द्वारा निकाली गयी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जन जागरूकता रैली को प्राचार्य प्रो.डॉ. संतोष सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रैली महाविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर जख्खिनी बाजार होते हुए लंबी लाइन में कतारबद्ध होकर

स्वयंसेवकों ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की नारा लगाते हुए नरसड़ा गांव में पहुंच कर वहा घर-घर जाकर बहू बेटियों को शिक्षित करने के लिए जागरूक करते हुए बताया कि बेटिया बेटों के समान है,बेटियां आधी आबादी है अगर वह शिक्षित होगी तो आने वाली पीढियां को भी शिक्षित करेगी। तत्पश्चात सभी स्वयंसेवकों ने नरसड़ा गांव के सड़क व गलियों तथा महाविद्यालय परिसर का साफ सफाई कर श्रमदान किया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक्सपोजर विजिट की दो बसों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पीएम श्री योजना के अंतर्गत बच्चों को व्यावहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से आज 2 फरवरी 2026 को जनपद जौनपुर

के पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षिक एक्सपोजर विजिट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 गोरखनाथ पटेल द्वारा एक्सपोजर विजिट हेतु लगी दो बसों को हरी झंडी दिखाकर बनास डेयरी (अमूल), फूलपुर, वाराणसी के लिए रवाना किया गया। इस शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्किल डेवलपमेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उद्यमिता की समझ तथा स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता विकसित करना रहा। भ्रमण के दौरान बच्चों ने यह भी जानकारी प्राप्त की कि भविष्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान दिया जा सकता है। शैक्षिक भ्रमण में जनपद के 38 पीएम श्री विद्यालयों के 100 चयनित छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों के साथ संबंधित विद्यालयों के शिक्षक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे भ्रमण के दौरान बच्चों का मार्गदर्शन एवं सहयोग किया।

एक्सपोजर विजिट के दौरान बच्चों ने अमूल डेयरी प्लांट में दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, छाछ एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। अमूल कंपनी के गाइड द्वारा बच्चों को प्रत्येक इकाई की कार्यप्रणाली, तकनीकी जानकारी एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया। बच्चों ने विशेष रूप से यह जाना कि आइसक्रीम, घी और दूध के विभिन्न उत्पाद किस प्रकार आधुनिक तकनीक से तैयार किए जाते हैं। शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों में उत्साह एवं जिज्ञासा देखने को मिली। सभी विद्यार्थियों ने इस अनुभव को ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और यादगार बताते हुए भविष्य में ऐसे शैक्षिक भ्रमण आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर जिला समन्वयक प्रशिक्षण विशाल कुमार, डीसी एमडीएम अरुण कुमार मौर्य, एसआरजी टीम सदस्य अजय कुमार मौर्य सहित जनपद के संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे।

केराकत पुलिस ने प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले चार व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। थाना केराकत पुलिस द्वारा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 04 व्यक्ति गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक दीपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में केराकत पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2026 धारा-3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन

प्रतिषेध अधिनियम में त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त के आरोपीगण अजय कुमार पुत्र राम नारायण निवासी तरियारी थाना केराकत जौनपुर, राजबली पुत्र भभूति निवासी बलईपुर थाना केराकत जौनपुर, दिवाकर पुत्र त्रिभुवन निवासी बरौना थाना बरदह जनपद आजमगढ़, अवधेश पुत्र अच्छेलाल निवासी मैरांद खान थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर को अभियुक्त अजय कुमार पुत्र राम नारायण निवासी तरियारी के घर से गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण का चालान न्यायालय कर अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

स्मार्ट मीटर व डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु विशेष जागरूकता अभियान

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद में विद्युत वितरण खंड बरईपुर, वाराणसी द्वारा सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर एवं डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 2 फरवरी 2026 से एक विशेष जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान उन उपभोक्ताओं के लिए संचालित किया जाएगा, जिनके परिसरों पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।अभियान के अंतर्गत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से संबंधित विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। इसमें नेगेटिव बैलेंस की स्थिति में रिचार्ज कराना, एडवांस बिल भुगतान, एरियर राशि का रिचार्ज के माध्यम से भुगतान, उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन में UPPCL Smart App डाउनलोड कराना, सही मोबाइल नंबर अद्यतन करना तथा नियमित रूप से बिजली बिल रिचार्ज करने हेतु प्रेरित करना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध भुगतान व्यवस्था से जोड़ना है।

इस विशेष अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल वाराणसी के निर्देशन में अधिशासी अभियंता द्वारा उपखंड अधिकारियों, अवर अभियंताओं एवं लाइनमैनों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान स्मार्ट मीटर संचालन, मोबाइल ऐप का उपयोग, उपभोक्ता संवाद कौशल तथा डिजिटल भुगतान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके।अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बरईपुर मनीष कुमार झा ने सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस जागरूकता अभियान में सक्रिय सहयोग करें और समय पर बिजली बिल का भुगतान कर विभागीय प्रयासों को सफल बनाएं।

मध्य प्रदेश रणजीत ट्रॉफी खिलाड़ी सुनील धौलपुरे को पितृ शोक

इंदौर (उत्तरशक्ति)। वाल्मिकी गौरव, प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर,म.प्र. रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी सुनील धौलपुरे,सचिन धौलपुरे के पूज्य पिता चौधरी सेठ मन्नूलाल धौलपुरे का आकस्मिक निधन हो गया हैं, जिनका अंतिम संस्कार 26 जनवरी 2026 को पंचकुइया मुक्तिधाम पर किया गया। स्व.धौलपुरे सरल,सहज,मृदुभाषी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के थे।समाज के लिए भी उन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। समाजिक कार्य में में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते थे। उनके निधन पर कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि ईश्वर परिवार वालों को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। यह जानकारी दैनिक उत्तर शक्ति समाचार पत्र के चीफ ब्यूरो प्रणीत तिवारी ने दी है।

निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण हो सड़क निर्माण : रमेश सिंह

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। विधायक रमेश सिंह ने सोमवार को खुटहन विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत पिलकिछा चौराहा स्थित पुरानी बाजार में निमार्णाधीन सीसी रोड का क्षेत्रवासियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। विधायक ने सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेरा निरंतर प्रयास है कि क्षेत्र में बनने वाली सभी सड़कें निर्धारित मानकों के अनुरूप, मजबूत एवं गुणवत्तापूर्ण हों। गुणवत्ता के साथ किया गया यह निर्माण कार्य क्षेत्रवासियों को सुगम, सुरक्षित एवं सुचारू आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। जनसुविधा और टिकाऊ विकास ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता की भी जिम्मेदारी है कि सड़क के निर्माण कार्य को अपने स्तर से परखें और यदि कोई समस्या हो तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहें। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के मानकों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर गूंजा नदियों के संरक्षण का संकल्प, नदियों को बचाने की अपील

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर नदियों और उनसे जुड़ी आर्द्रभूमियों के संरक्षण को लेकर काशी में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम स्थित गंगा द्वार पर नमामि गंगे अभियान के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से नदियों को जीवनदायिनी बताते हुए उनके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश दिया गया कि नदियाँ और उनसे जुड़ी आर्द्रभूमियां हमारे साझा भविष्य की आधारशिला हैं। इनके बिना न केवल जल संकट गहराएगा, बल्कि जैव विविधता, पर्यावरण संतुलन और आजीविका पर भी गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि समय की मांग है कि जल प्रदूषण को रोका जाए, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखा जाए और आर्द्रभूमियों को अतिक्रमण व विनाश से बचाया जाए।

कैश वैन ट्रक की टक्कर से पलटी, रूपया सुरक्षित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के सरोखनपुर फोरलेन पर सोमवार दोपहर एक बडा हादसा हुआ। रुपयों से भरी एक कैश वैन अज्ञात ट्रक की टक्कर से सडक पर पलट गई। गनीमत की बात यह रही कि कैश वैन में सवार चालक सहित सभी सुरक्षाकर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार, वाराणसी से कैश वैन सेंट्रल बैंक की सुईथाकला शाखा के लिए नकदी लेकर जा रही थी। वैन को चालक अमित कुमार सिंह चला रहे थे। सरोखनपुर फोरलेन पर पहुंचते ही पीछे से आए एक अज्ञात ट्रक ने कैश वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बदलापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शेष कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कैश वैन को कब्जे में लिया और उसे थाने भिजवाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कैश पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है।

बरसठी में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत

-दिनेश विश्वकर्मा

बरसठी जौनपुर (उत्तरशक्ति)। थाना बरसठी क्षेत्र में शनिवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अज्ञात बोलेरो वाहन चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कुंदनपुर निवासी रामसरे पटेल पुत्र लक्ष्मीमूरत पटेल ने थाना बरसठी में तहरीर देकर बताया कि दिनांक 01 फरवरी 2026 को रात्रि लगभग 09 बजे, ग्राम गहलाई के पास लगभग 10 किलोमीटर पूर्व, एक अज्ञात बोलेरो वाहन चालक ने तेज व लापरवाह गति से वाहन चलाते हुए उनके भतीजे अनंद उर्फ सोनू की मोटरसाइकिल संख्या वढ 62 उल्ठ 5964 में जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में अनंद उर्फ सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए चिकित्सक के पास ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर थाना बरसठी में मु0अ0सं0 0018/2026, धारा 281, 125( ), 106(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, अज्ञात बोलेरो वाहन व उसके चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

18 वर्ष पूरे कर चुके छात्र-छात्राएं बनेंगे मतदाता,विद्यालयों को फॉर्म भरवाने के निर्देश

हरदोई(उत्तरशक्ति)। मतदाता सूची को अधिक से अधिक सटीक और व्यापक बनाने के उद्देश्य से चल रहे पुनरीक्षण अभियान के तहत अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके छात्र-छात्राओं को मतदाता सूची में शामिल करने की कवायद और तेज कर दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि कोई भी पात्र युवा अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रा, जिनकी आयु एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनके फॉर्म-06 भरवाए जाएं। भरे हुए फार्म के साथ घोषणा पत्र संलग्न कर संबंधित कार्यालय में समय से जमा कराया जाए, जिससे उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय स्तर पर इस कार्य को गंभीरता से लिया जाए और पात्र छात्र-छात्राओं को मतदाता बनने के प्रति जागरूक भी किया जाए। इसके अलावा छात्र-छात्राओं को यह सुविधा भी दी गई है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर स्वयं भी फॉर्म-06 भर सकते हैं। निर्वाचन विभाग का मानना है कि विद्यालयों के माध्यम से अभियान चलाने से बड़ी संख्या में नए मतदाताओं को जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि युवा पीढ़ी में मतदान के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की है कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग कर अधिक से अधिक पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कराने में भूमिका निभाएं।

एसआरए के अटके प्रकल्प युद्ध स्तर पर पूरे करे सरकार : बाबूभाई भवानजी

मुंबई। वरिष्ठ भाजपा नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवानजी ने राज्य सरकार से मांग की है कि एसआरए (स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी) के तहत जिन झोपड़पट्टी परियोजनाओं के लिए भूमि खाली कराई जा चुकी है, लेकिन वर्षों से काम अटका हुआ है, उन्हें युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी के कारण हजारों झोपड़पट्टीवासियों का जीवन अंधकारमय हो गया है।

भवानजी ने कहा कि सरकार को इस मामले में सक्रिय दखल देते हुए झोपड़पट्टीवासियों को सम्मानपूर्वक घर, दुकान और कार्यालय उपलब्ध कराने चाहिए। साथ ही, एसआरए योजनाओं में बने अतिरिक्त आवासों को नो प्रॉफिटझनो लॉस के आधार पर मध्यम वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इस बीच महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में मुंबई को झोपड़पट्टी-मुक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में घोषणा की कि मुंबई में 17 स्थानों पर एसआरए क्लस्टर पुनर्विकास परियोजनाएं लागू की जाएंगी। इसके तहत 50 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले निजी, शासकीय और अर्ध-शासकीय भूखंडों पर एकीकृत पुनर्विकास किया जाएगा।

पहले चरण में अंटापहिल, बोरीवली के कृष्णा नगर और केतकीपाड़ा, दहिसर का गोपीकृष्ण नगर, ओशिवरा, गोवंडी, ट्रॉम्बे का चिट्टा कैंप, चेंबूर, विक्रोली के टैगोर नगर और पार्कसाइट तथा भांडुप सहित कुल 17 प्रमुख क्षेत्रों का चयन किया गया है। आगे अन्य झोपड़पट्टियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे झोपड़पट्टीवासियों के साथ-साथ मध्यम वर्गीय परिवारों को भी मुंबई में किफायती आवास मिल सकेगा।

भवानजी ने जानकारी दी कि मुंबई की झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास के लिए राज्य सरकार व्यापक सर्वेक्षण कराएगी। इसी क्रम में, झोपड़पट्टीवासियों को सर्वे के दौरान आवश्यक दस्तावेज (ऑनलाइन/ऑफलाइन) तैयार रखने के लिए दादर (पूर्व) स्थित अपने कार्यालय से मार्गदर्शन अभियान शुरू किया गया है।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया कि छोटे-छोटे एसआरए प्रकल्पों के बजाय अब क्लस्टर रिडेवलपमेंट मॉडल के माध्यम से पूरे क्षेत्रों का कायाकल्प किया जाएगा। इस नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी थी और संबंधित शासन निर्णय 13 नवंबर 2025 को जारी किया गया। परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एमएमआरडीए, सिडको, एमआईडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा और बीएमसी के साथ जॉइंट वेंचर मॉडल अपनाया जाएगा। इसके अलावा, एसआरए की अभय योजना को अब 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार उन नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है जो झोपड़ियों की खरीद-फरोख्त या हस्तांतरण से जुड़ी तकनीकी अड़चनों के कारण पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पा रहे थे। साथ ही, म्हाडा की ओसी (ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट) से जुड़ी अभय योजना को भी एक वर्ष का विस्तार दिया गया है। झोपड़पट्टी पुनर्विकास से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए गठित एपेक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी (एजीआरसी) की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 2,103 मामले लंबित हैं, जिनके शीघ्र समाधान के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही, बीएमसी लीज प्लॉट पर बने महापालिका कर्मचारियों के आवासों के लिए नई योजना लाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुलुंड में मुफ्त चिकित्सा शिविर का भव्य आयोजन

मुंबई। मुलुंड के केशवपाड़ा स्थित कपिल क्लीनिक में रविवार को एक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फोर्टिस अस्पताल के कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। इस शिविर का आयोजन डॉ. सचिन सिंह और डॉ. प्रिया भानुशाली के नेतृत्व में किया गया। डॉ. सचिन सिंह ने कहा कि ऐसे शिविर जरूरतमंद लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं तथा समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिविर में नेत्र परीक्षण, रक्तचाप, शुगर जांच, ईसीजी जैसी सेवाएं दी गईं, वहीं सस्ती दरों पर चश्मा भी उपलब्ध कराया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने शिविर की सेवाओं का लाभ उठाया। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस सचिव राजेश इंगले, वीरेंद्र चतुर्वेदी, एन. के. सिंह, जयबाला सिंह, डॉ. नेहा सिंह, डॉ. आर. एम. पाल, चंद्रवीर यादव, राजकुमार यादव, मनोज सिंह, मोहित सिंह, एड. शरीफ खान सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान स्व. डॉ. बाबूलाल की कमी को मुलुंडवासियों ने भावुक होकर याद किया।

गधियाँवा से प्रयागराज माघी कुंभ 2026 में नि:शुल्क बस सेवा संपन्न

प्रतापगढ़। माघी कुंभ 2026 के पावन अवसर पर प्रतापगढ़ पट्टी के ग्राम गधियाँवा से प्रयागराज संगम स्नान हेतु आयोजित निःशुल्क बस सेवा का आयोजन शनिवार को पूरी श्रद्धा, सेवा-भाव और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद आस्था का उत्साह कम नहीं हुआ और सुबह 7 बजे ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होकर संगम स्नान के लिए रवाना हो स्नान कर वापस लौटे ।

इस पुनीत सेवा के आयोजक में दिनेश पांडेय,आलोक पांडेय व अविनाश पांडेय रहे और आयोजक के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था अनुशासित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रही। निःशुल्क बस सेवा ने विशेषकर ग्रामीण श्रद्धालुओं के लिए कुंभ स्नान को सुलभ बनाया और उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। यात्रा के आयोजक समाजसेवक व भजन गायक दिनेश कुमार पांडेय ने कहा, माघी कुंभ केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का संगम है। गधियाँवा से प्रारंभ हुई यह निःशुल्क बस सेवा समाज की सामूहिक चेतना और सहयोग की भावना को दशार्ती है।ह्व ग्राम वसियों के सुविधाओं हेतु हम लगातार कार्य कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे । इस आयोजन के निवेदक समस्त ग्रामवासी, गधियाँवा रहे। श्रद्धालुओं एवं ग्रामवासियों ने इस सफल आयोजन के लिए आयोजक और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे समाजसेवा और सनातन परंपरा की प्रेरणादायी मिसाल बताया।

जसलोक अस्पताल ने सटीक निदान के महत्व पर दिया जोर

मुंबई। जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने एक जटिल न्यूरोलॉजिकल मामले में सटीक, साक्ष्य-आधारित चिकित्सा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 35 वर्षीय नर्स को गंभीर और आजीवन चलने वाले गलत इलाज से सुरक्षित बचाया। एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज को मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी गंभीर न्यूरोमस्कुलर बीमारी से पीड़ित मान लिया गया था और लंबे समय के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं शुरू कर दी गई थीं। हालांकि, जसलोक अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा किए गए गहन मूल्यांकन और आधुनिक न्यूरोफिजियोलॉजिकल परीक्षणों से यह स्पष्ट हुआ कि मरीज को मायस्थेनिया ग्रेविस नहीं था। नवी मुंबई की रहने वाली यह मरीज पिछले कई महीनों से बाईं पलक के झपकने या नीचे झुकने (पोसिस) की समस्या से परेशान थीं। पहले से हाइपरथायरायडिज्म से जूझ रही इस युवा महिला ने मुंबई के एक अस्पताल में परामर्श लिया, जहाँ एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आने के आधार पर उन्हें मायस्थेनिया ग्रेविस का निदान कर दिया गया और स्टेरॉयड तथा पाइरिडोस्टिग्माइन जैसी दवाएं शुरू कर दी गईं। इन दवाओं के लंबे समय तक सेवन से विशेष रूप से युवा महिलाओं में गंभीर दुष्प्रभाव और प्रजनन संबंधी जोखिम हो सकते हैं।

हाइपरथायरायडिज्म के शारीरिक और मानसिक दबाव के बीच, आजीवन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की आशंका से मरीज की चिंता और बढ़ गई। एक करीबी मित्र की सलाह पर उन्होंने सेकंड ओपिनियन के लिए जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का रुख किया, जहाँ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर विशेषज्ञ डॉ. विनया भंडारी ने मामले का पुनर्मूल्यांकन किया। जसलोक अस्पताल में की गई विस्तृत जांच में ब्रेन एमआरआई के जरिए यह स्पष्ट किया गया कि पलक झपकने की समस्या किसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम विकार से संबंधित नहीं थी। इसके बाद रिपिटेटिव नर्व स्टिम्युलेशन और विशेष रूप से सिंगल-फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी (SFEMG) जैसे उन्नत परीक्षण किए गए। SFEMG, मायस्थेनिया ग्रेविस के निदान के लिए सबसे संवेदनशील और सटीक जांच मानी जाती है—और इस मामले में इसके परिणाम पूरी तरह सामान्य पाए गए। डॉ. विनया भंडारी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर विशेषज्ञ, जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने कहा, सिंगल-फाइबर ईएमजी उन मरीजों में सबसे संवेदनशील जांच है जिनमें पोसिस, डबल विजन, बोलने या निगलने में कठिनाई और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यदि प्रभावित मांसपेशी का SFEMG सामान्य आता है, तो मायस्थेनिया ग्रेविस होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इन निष्कर्षों के आधार पर मरीज की मायस्थेनिया ग्रेविस की सभी दवाएं तुरंत बंद कर दी गईं। आगे की जांच में यह सामने आया कि लगातार खुजली के कारण मरीज अपनी बाईं पलक को बार-बार रगड़ती थीं, जिससे उन्हें ट्रॉमेटिक एपोन्यूरोटिक पोसिस हो गया था।

ग्रामीण विकास के साथ सनातन धर्म का प्रसार करनेवाले पीठाधीश्वर रिंकू महाराज का सम्मान

जौनपुर। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान राहुल एजुकेशन द्वारा आज गुरुजी ग्रामीण विकास के साथ-साथ अमेरिका तक सनातन धर्म का प्रसार करने वाले बड़कू हनुमान जी महाराज मंदिर एवं पीठाधीश्वर रिंकू महाराज का पुरेव स्थित हनुमान मंदिर पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी जलालपुर गजानन चौबे, समाजसेवी रामजी उपाध्याय, हरिवंश उपाध्याय उपस्थित रहे। राहुल एजुकेशन की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन पांडे ने धार्मिक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया।

रिंकू महाराज और उनके परिवार के 156 लोग अमेरिका रहते हैं। 12 वर्ष की उम्र में अध्यात्म से जुड़ने वाले रिंकू महाराज ने सनातन धर्म के प्रसार के साथ ग्रामीण विकास का संकल्प लेकर सेवा भावना के साथ लगातार काम कर रहे हैं। 38 वर्षीय अविवाहित संत रिंकू महाराज राजनीति से परहेज नहीं करते। उनका मानना है कि अगर आपको जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करना है और गांवों का विकास करना है तो राजनीति एक सशक्त माध्यम है।

रिंकू महाराज ने अमेरिका में 108 ताकतवर लोगों को ट्रस्टी बनाया है, जिसमें राजेश अग्रवाल , डॉ रीता अग्रवाल जैसे प्रख्यात उद्योगपति शामिल हैं। गांव में उन्होंने राजाराम हॉस्पिटल की स्थापना की है, जिसमें आम मरीजों को 50% डिस्काउंट पर इलाज की सुविधा है। किसानों को लेकर रिंकू महाराज के पास अनेक दूरदर्शी योजनाएं हैं। हर गांव में कोल्ड स्टोर की स्थापना से लेकर हर घर में लघु उद्योग की स्थापना करना उनका मिशन है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुद्रा दायिनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा उनके निर्यात के लिए समुचित संसाधनों का उपयोग किया उनकी दूरदर्शी योजनाओं में शामिल है। ग्रामीण विकास को लेकर अपने दूरदर्शी योजनाओं क्रियान्वित करने के लिए वे विधानसभा चुनाव में भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

जौनपुर को 944.19 करोड़ के वेस्टर्न बाईपास की बड़ी सौगात

सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने रिंग रोड के निर्माण को लेकर केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर के सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने रविवार को 944.19 करोड़ के वेस्टर्न बाईपास की बड़ी सौगात दी है जिसमें दोनों तरफ सर्विस रोड शामिल हैं। सांसद के प्रयास से जनता को आवागमन में सुविधा एवं सहूलियत मिलेगी।

जौनपुर सदर के सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से शहर के 12.2 कमी लंबे 4 लेन वेस्टर्न बाईपास के निर्माण के लिए मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए 944.19 करोड रुपए की स्वीकृति दे दी है। यह परियोजना मार्ग एक कंटीन्यूअस रिंग रोड बनाकर जौनपुर के क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क में मिक्सिंग लिंग को पूरा करेगा। इससे शहर में लगने वाले भीषण जाम से निजात मिलेगी। सांसद ने बताया कि इससे शहर का ट्रैफिक सुगम होगा। इसके अलावा इससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सांसद ने कहा कि जनपद की जनता को लंबे समय से आवागमन में जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था। इसका इंतजार जनता लंबे अरसे से कर रही थी। हमारा प्रयास जनता की समस्याओं को दूर करना है। आम जनता के हितों और उम्मीदों पर खरा उतरना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

इस बजट में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित : साक्षी गुप्ता

पटना (उत्तरशक्ति)। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, बजट घरेलू विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक मध्यम अवधि का रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित है। पिछले बजट के विपरीत, जिसमें आयकर युक्तिकरण के माध्यम से उपभोग को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई थी, इस बजट में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उक्त बातें एचडीएफसी बैंक की प्रधान अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने वित्त वर्ष 2027 के बजट पर टिप्पणी करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना, वैश्विक सेवाओं में भारतीय सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सरकार के नीतिगत जोर को रेखांकित करती है। वित्त मंत्री की विकसित भारत योजना में घरेलू उत्पादन, बुनियादी ढांचे के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ पृथ्वी चुंबक और रसायन को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा, कपड़ा और लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को, जिन पर शुल्क का बोझ अधिक था, अधिक नीतिगत समर्थन प्रदान किया गया। राजकोषीय गणित की दृष्टि से, बजट वित्त वर्ष 2027 के लिए 10 प्रतिशत नाममात्र जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाकर रूढ़िवादी बना हुआ है, जो हमारे 10.5 प्रतिशत के अनुमान से कम है। पूंजीगत व्यय लक्ष्य के संबंध में, सरकार ने उम्मीद के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 में 11.5 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि का लक्ष्य रखा है और निजी पूंजी को आकर्षित करने पर भरोसा जताया है।

वित्तीय गणित मोटे तौर पर विश्वसनीय और विवेकपूर्ण प्रतीत होता है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 27 के लिए सौम्य राजकोषीय सुदृढ़ीकरण है। हालांकि, उम्मीद से अधिक 17.2 लाख करोड़ रुपये के सकल उधार से बाजार की भावनाओं पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि मांग और आपूर्ति में असंतुलन पहले से ही बॉन्ड यील्ड पर दबाव डाल रहा है। हमें उम्मीद है कि कल 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड अधिक के साथ खुलेगी।

जब पेशे से आगे बढ़कर करुणा बनी पहचान

अंतरराष्ट्रीय मंच पर काशी की सीए सुदेशना बसु को वुमेन्स एक्सीलेंस अवॉर्ड

-सुरेश गांधी

वाराणसी. ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इस वर्ष कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में भारत सहित दुनिया भर के लगभग दस हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भाग लेकर लेखा, वित्त और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े विमर्श को नई दिशा दी।

इसी भव्य आयोजन के समापन सत्र में काशी की वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट और समाजसेवी सीए श्रीमती सुदेशना बसु को Women's Excellence Award से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किसी कॉर्पोरेट उपलब्धि या आर्थिक नवाचार के लिए नहीं, बल्कि सड़कों पर बेसहारा, घायल और बीमार पशुओं की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रदान किया गया—जो अपने आप में इस सम्मेलन की सबसे संवेदनशील और प्रेरक उपलब्धि रही।

कानून, संस्कृति और समाज के संगम पर सम्मान

सम्मान समारोह के दौरान भारत के केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री तथा संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी ने अपने कर-कमलों से सीए सुदेशना बसु को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब काशी की एक बेटी का नाम सामाजिक करुणा और सेवा के लिए गूंजा, तो यह क्षण केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल और काशी की सांस्कृतिक चेतना के लिए गौरवपूर्ण बन गया।

जब अकाउंट्स से आगे बढ़कर इंसानियत बोली

सीए सुदेशना बसु वर्षों से वाराणसी की सड़कों पर घायल,

बीमार और त्यक्त पशुओं के उपचार, संरक्षण और पुनर्वास के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रही हैं। व्यस्त पेशेवर जीवन के बावजूद उन्होंने यह सिद्ध किया कि संवेदनशीलता समय या सुविधा की मोहताज नहीं होती। कई बार आधी रात को घायल पशु के इलाज के लिए निकल पड़ना, स्वयं संसाधन जुटाकर उपचार कराना और समाज को पशु कल्याण के प्रति जागरूक करना—यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी यह सेवा न तो प्रचार की आकांक्षा से प्रेरित रही, न ही किसी मंच की अपेक्षा से। शायद इसी निस्वार्थ भाव ने उन्हें आज अंतरराष्ट्रीय सम्मान तक पहुंचाया।

काशी के लिए गौरव, समाज के लिए संदेश

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पेशेवर उत्कृष्टता और सामाजिक जिम्मेदारी एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। काशी, जो सदियों से करुणा, सह-अस्तित्व और जीवदया की भूमि रही है, आज उसी परंपरा को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ते हुए देख रही है। सीए सुदेशना बसु की यह उपलब्धि विशेष रूप से युवाओं और पेशेवर वर्ग के लिए प्रेरणा है कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल आर्थिक ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि समाज के सबसे असहाय वर्ग—चाहे वह इंसान हो या पशु—के प्रति संवेदनशील होने में निहित है।

अंतरराष्ट्रीय मंच से उठा मानवीय स्वर

वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स जैसे वैश्विक मंच पर जब पशु सेवा जैसे विषय को सम्मान मिला, तो यह सम्मेलन के उद्देश्य को भी व्यापक बनाता है। यह दशार्ता है कि आज की वैश्विक सोच केवल बैलेंस शीट और मुनाफे तक सीमित नहीं, बल्कि करुणा, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान महत्व देती है। सीए सुदेशना बसु का सम्मान इस बात का प्रमाण है कि काशी केवल मोक्ष की नगरी ही नहीं, बल्कि करुणा की जीवंत प्रयोगशाला भी है—जहां सेवा, संवेदना और संस्कार आज भी सांस लेते हैं।

औद्यानिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला उद्यान अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद के किसानों को राजधानी लखनऊ के राजभवन (जनभवन) में आयोजित होने वाली प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी में अपनी उपज प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। यह प्रदर्शनी आगामी 6 फरवरी से 8 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राजकीय प्रदर्शनी में जनपद के विभिन्न ब्लॉक से किसान अपने उत्पादों के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के उत्कृष्ट नमूनों का प्रदर्शन किया जाएगा। शहद एवं मशरूम, विभिन्न प्रकार के पुष्प और सजावटी पौधे ताजे फल एवं हरी सब्जियां पॉली हाउस में पैदा किए गए बेमौसमी पुष्प और सब्जियां जौनपुर की विशिष्ट बागवानी फसलें संरक्षित पदार्थ, रंगोली कलात्मक पुष्प सज्जा वर्टिकल गार्डेन एवं फोटोग्राफी आदि वर्गो की प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। इस वर्ष विभिन्न वर्गो में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विजेता को रू0 5100 की नगद धनराशि एवं वैजन्ती कप प्रदान की जायेगी प्रदर्शनी का शुभारम्भ द्वारा 06 फरवरी को जन भवन प्रांगण लखनऊ में आवेदन की प्रक्रियारू इच्छुक किसान अपनी फसल के साथ प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए किसानों को विभाग के निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए मात्र 10 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे जमा कर किसान अपना प्रतिभागी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। प्रदर्शनी में भाग लेने के इच्छुक किसानों को अपनी प्रविष्टियों के साथ 5 फरवरी की सुबह 11 बजे तक निर्धारित स्थल राजभवन (जनभवन) लखनऊ पर पहुँचना होगा। वहां निर्णायक मंडल द्वारा प्रदर्शनी की जांच की जाएगी और परिणाम घोषित होने के बाद सफल किसानों को सम्मानित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई जनपद के जिला उद्यान कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

मुलुंड मैराथन 2026 का सफल आयोजन

इस मैराथन में 375 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कई अभिभावकों ने भी अपने बच्चों के साथ दौड़ में हिस्सा लिया, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी सकारात्मक व प्रेरणादायक बन गया। प्रतियोगिता के अंतर्गत 1 किमी, 3 किमी और 5 किमी की दौड़ श्रेणियां रखी गई थीं। 1 से 7 वर्ष आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से 1 किमी दौड़ आयोजित की गई, जबकि 7 से 12 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए 3 किमी और 5 किमी की दौड़ रखी गई थी। कुल मिलाकर इस मैराथन में लगभग 5 अलग-अलग श्रेणियां शामिल थीं। मैराथन की शुरूआत और समापन लायंस क्लब, मुलुंड में हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र, पदक और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आदर्श सूत्रसंचालन विजयलक्ष्मी ने किया।

मुंबई। 1 फरवरी को लायंस क्लब, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई में मुलुंड मैराथन का सफल आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्रख्यात समाजसेवी डॉ.बाबुलाल सिंह को डॉ.आर आर सिंह, समाजसेवी महानंद सिंह, पाल समाज अध्यक्ष राजाराम पाल , डॉआर .एम . पाल, ऑल इंडिया यादव महासभा महासचिव शिक्षाविद् चंद्रवीर बंशीधर यादव , लेखक राजकुमार रामलखन यादव, समाजसेवी सुरेंद्र मिश्रा, विनय त्रिपाठी ,राकेश दुबे,रोहीदास देवाडे,रमाशंकर पाल, अधिवक्ता शरीफ खान ,समाजसेविका वंदना राजधर पांडे सहित सैकड़ों गणमान्यों ने श्रद्धांजली दी.इस मैराथन का आयोजन आशिहारा कराटे इंडिया के महाराष्ट्र चीफ दयाशंकर पाल के मार्गदर्शन में किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों में फिटनेस, अनुशासन और सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना था।

लोढ़ी टोलप्लाजा की घटनाओं से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन

रेणुकूट ,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। लोढ़ी में एक महिला अधिवक्ता एव उनके साथियों पर टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा किये गए मारपीट में कार्यवाई को लेकर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तहसील मोड़ पर सोमवार को दुद्धी बार एसोसिएशन एवं सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता टोल प्लाजा लोढ़ी में एक महिला अधिवक्ता व उनके साथियों के साथ भी मारपीट की घटना से आक्रोशित होकर निंदा करते हुए जिला प्रशासन से मांग कर कहा कि, दोषी टोल प्लाजा कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। टोल प्लाजा द्वारा मनमानी तरीके से टैक्स वसूली पर रोक लगाई जाए। यह टोल प्लाजा लूटपाट का केंद्र बना हुआ है। 50 किलोमीटर से कम दूरी पर दो टोल प्लाजा स्थित है। जो कानून गलत है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए। संयुक्त बार एसोसिएशन ने उपजिलाधिकारी नामित ज्ञापन एसडीएम दुद्धी निखिल यादव को सौंपा। इस अवसर पर सिविल बार अध्यक्ष प्रभु सिंह कुशवाहा, कुलभूषण पांडेय, रामजी पांडेय, राकेश श्रीवास्तव, रामपाल जौहरी सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे।

स्वर्गीय बाबू सहदेव प्रसाद महतो बिंद ट्रॉफी का होगा महामुकाबला 8 फरवरी को

स्वर्गीय बाबू सहदेव प्रसाद महतो बिंद ट्रॉफी का महामुकाबला 8 फरवरी को

मुंबई (उत्तर शक्ति)। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बिंद समाज विकास संघ के तत्वावधान में महान समाज सुधारक स्वर्गीय बाबू सहदेव प्रसाद महतो बिंद की स्मृति में बी.एस.वी.एस. प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता 8 फरवरी, दिन रविवार, को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आचार्य मैदान, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई में आयोजित होगी। मैदान पंतनगर पुलिस स्टेशन बस स्टॉप के समीप स्थित है।

आयोजकों ने सर्व समाज के क्रिकेट प्रेमियों से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर विभिन्न राज्यों से भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और रोमांचक क्रिकेट मुकाबलों का आनंद लें, जिससे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। इस महा मुकाबले में कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें प्रमुख रूप से वर्ली ब्लास्टर, सूरत स्ट्राइकर, कुर्ला अवेंजर, विद्या विहार रॉयल, जोगेश्वरी राइडर, वसई टाइगर, जी.एस.के. घाटकोपर किंग, सायन सुपर-11, टिटवाला इंडियन, विक्रोली एक्सप्रेस, वाहन सेना, सुपरफास्ट कांदिवली चैंपियंस शामिल हैं। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों एवं सहयोग करने वाले समाजसेवियों को बिंद समाज विकास संघ द्वारा सर्टिफिकेट एवं सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

प्रतियोगिता में विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। जिसमें प्रथम पुरस्कारः 15,555, द्वितीय पुरस्कारः 11,11, तृतीय पुरस्कारः 5,555 रुपए शामिल है। इसके अलावा प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन एवं बेस्ट बॉलर को चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अन्तर्गत कार्यालय क्षेत्र पंचायत सिरकोनी विधानसभा क्षेत्र 371 जफराबाद और कार्यालय क्षेत्र पंचायत जलालपुर पर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र द्वारा मतदाता सूची से संबंधित कार्यवाहियों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया कि मा० भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनमैप्ड मतदाताओं से संबंधित नोटिसों की तामील प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित बीएलए से संवाद करते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 भरने एवं जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। बीएलए द्वारा बताया गया कि बीएलओ एवं सुपरवाइजरों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। जिलाधिकारी ने बताया कि सुनवाई की समुचित व्यवस्था की गई है। मतदाता स्वयं उपस्थित होकर अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आवश्यक साक्ष्यों सहित अपना पक्ष रख सकते हैं। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे बीएलओ के कार्यों में सहयोग करें तथा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाणित कर फॉर्म-6, 7 एवं 8 स्वतः जमा कराएं।

इस दौरान उन्होंने उपस्थित ग्रामवासियों से वार्ता करते हुए कहा कि जिनको भी नोटिस निर्गत किया गया है वे नियत तिथि पर अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना साक्ष्य मिलान करा ले। इसमें एईआरओ द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित ईआरओ, बीएलओ तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के बीएलए, ग्रामवासी उपस्थित रहे।

करंट की चपेट में आने से संदीप निषाद की मौत

मुंबई। शुक्रवार को संदीप पुत्र अलगू राम निषाद उम्र 38 की मांगली पाड़ा , वाघराल पाड़ा, वसई पूर्व पालघर मुंबई महाराष्ट्र में बिजली के खंभे में प्रवाहित हो रही करंट की चपेट में आने से संदीप निषाद पूरी तरह झुलस गया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। संदीप पुत्र अलगू राम निषाद ग्रामसभा हिंदुआ बाद, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। वसई मुंबई में रहकर अपने परिवार का हार्डवर्क कर-के पालन पोषण करते थे। बिजली विभाग के इस लापरवाही को देखते हुए, मृतक के परिवार वालों ने बच्चों की पढ़ाई भरण पोषण के लिए मुवावजे की मांग की है। वसई रहवासियों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी उत्पन्न हो गई है। परिवार एवं पास पड़ोसियों ने आरोप लगाया है कि अगर इस तरह की लापरवाही को रोका नहीं गया तो यहां आम जनता की आवागमन भरपूर तादाद में रहती है और भी जान जाने का खतरा बना है।

किआ इंडिया ने जनवरी में 27,603 गाड़ियों की बिक्री की

मुंबई। किआ इंडिया, देश की प्रमुख मास-प्रीमियम ऑटोमेकर कंपनियों में से एक, ने कैलेंडर वर्ष 2026 की सकारात्मक शुरूआत की है। कंपनी ने जनवरी में कुल 27,603 गाड़ियां बेंची और जनवरी 2025 में बेची गई 25,025 कारों की तुलना में इसमें 10.3% की वार्षिक वृद्धि हुई। यह प्रदर्शन कंपनी के स्थायी विकास, प्रमुख सेगमेंट्स में मजबूत मांग और भारतीय उपभोक्ताओं के बीच किआ के अलग-अलग उत्पादों की बढ़ती पसंद को दशार्ता है। जनवरी में कंपनी की बिक्री की गति इसके पोर्टफोलियो में लगातार मांग से प्रेरित रही, जिसमें ऑल-न्यू किआ सेल्टोस को मिली उत्साहजनक बाजार प्रतिक्रिया, किआ सोनेट का स्थिर प्रदर्शन और किआ कैरेंस क्लैविस तथा क्लैविस ईवी के लिए ग्राहकों का निरंतर आकर्षण शामिल है। नई पीढ़ी की सेल्टोस भारत के सबसे प्रभावशाली मिड-साइज एसयूवी में से एक के रूप में अपनी विरासत पर आधारित है और किआ इंडिया के अगले विकास चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सोनेट कॉम्पैक्ट स्वश सेगमेंट में किआ की मजबूत स्थिति को और मजबूत कर रहा है। कैरेंस मॉडल्स ने किआ को फैमिली कार और इलेक्ट्रिक कार के क्षेत्र में और मजबूत बनाया है। यह दिखाता है कि ग्राहक अब ज्यादा बहुपयोगी और भविष्य के लिए तैयार गाड़ियां चाहते हैं।

मासिक प्रदर्शन के बारे में, किआ इंडिया के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, अतुल सूद ने कहा, 2026 की यह शानदार शुरूआत दिखाती है कि ग्राहक किआ ब्रांड पर लगातार भरोसा कर रहे हैं। नई पीढ़ी की सेल्टोस को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया, सोनेट की स्थिर मांग और कैरेंस क्लैविस तथा क्लैविस ईवी की बढ़ती लोकप्रियता हमारे पोर्टफोलियो की ताकत और संतुलन पर जोर देती है। यह प्रदर्शन विभिन्न सेगमेंट्स में अच्छी तरह से अलग-अलग, भविष्य के लिए तैयार उत्पाद पेश करने पर हमारे फोकस को मजबूत करता है, साथ ही समग्र ओनरशिप अनुभव को लगातार बेहतर बना रहा है। किआ का पोर्टफोलियो डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर मजबूत फोकस के कारण अलग और विशिष्ट बना हुआ है। नई पीढ़ी की सेल्टोस और सोनेट अपने-अपने सेगमेंट में एडवांस्ड कनेक्टिविटी और ड्राइवर-असिस्टेंस फीचर्स प्रदान करते हैं, जबकि कैरेंस क्लैविस लचीले 6-और 7-सीटर कॉन्फि गरेशन तथा वसेर्टाइल तीन-पंक्ति वाले केबिन के साथ अलग पहचान बनाता है। वहीं किआ का भारत में निर्मित पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लैविस ईवी एक व्यावहारिक 7-सीटर ईवी पेशकश है, जिसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज के साथ-साथ कम्फर्ट, सेफ्टी और रोजमर्रा के उपयोगिता पर मजबूती से ध्यान दिया गया है। एक अच्छे और संतुलित प्रोडक्ट रेंज के साथ, किआ इंडिया अगले महीनों में भी अच्छी बिक्री और ग्रोथ जारी रखने की मजबूत स्थिति में है।

मदर्स रेसिपी ने कोरियाई जायके वाली रेसिपी अपनी नई डिजिटल वीडियो सीरीज लॉन्च की

मुंबई/पुणे। मदर्स रेसिपी ऐसा स्वदेशी ब्रांड है जिस पर भारतीय परिवार कई पीढ़ियों से भरोसा करते आए हैं। ब्रांड ने अब कोरियाई तरीके से खाना पकाने की कला को रोजाना के भारतीय किचन का हिस्सा बनाने के लिए एक नई डिजिटल फर्स्ट रेसिपी वीडियो सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में ऐसी रेसिपी पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो जल्दी समझ आने वाली, आसानी से बनने वाली और भारतीय किचन के लिए एकदम सही हैं। इसमें दिखाया गया है कि, जटिल सामग्रियों या लंबी तैयारी के बिना भी दुनिया भर के जायकेदार व्यंजन घर पर बड़ी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। आजकल कोरियाई जायके वाले व्यंजन लोगों के खाना ऑर्डर करने, रेसिपी देखने और खाना पकाने के तरीकों में सबसे पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं, साथ ही घर पर खाना पकाने वाले ज्यादातर लोग इसे बनाने का ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं, जो आसान और जाना-पहचाना हो। इसे जानने के बारे में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए ही यह कैंपेन शुरू किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि, कैसे कुछ भरोसेमंद सॉस की मदद से कुकिंग को मुश्किल बनाए बिना भी मनपसंद स्वाद वाले व्यंजन तैयार किया जा सकते हैं। यह कैंपेन खान-पान के प्रति आज के युवाओं के बदलते नजरिये को दिखाता है। उन्हें नए-नए व्यंजनों का आनंद लेना अच्छा लगता है, साथ ही उन्हें ऐसी रेसिपी की तलाश रहती है जो भागदौड़ भरी जिंदगी के हिसाब से हों और जिन्हें बनाकर उन्हें खुशी मिले।

यह कैंपेन मॉम-फूः माँ का प्यार अब कोरियन अवतार में की थीम पर आधारित है, जिसमें कोरियन स्पाइसी पनीर, कोरियन स्पाइसी नूडल्स, कोरियन बिबिम्बैप, कोरियन फ्राइड राइस और कोरियन वेज डकगाल्बी जैसी पाँच रेसिपी के वीडियो शामिल हैं, जो भारतीय किचन में कोरियाई स्वाद का जादू बिखेरना आसान बना देते हैं। इस सीरीज में सोयाबीन सॉस, गार्लिक चिली सॉस और रेड चिली सॉस से बना कोरियन स्पाइसी पनीर; देसी शेजवान सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोयाबीन सॉस और चिली विनेगर से बने कोरियन स्पाइसी नूडल्स; तथा चिली विनेगर और सोयाबीन सॉस से बनाया गया कोरियन बिबिम्बैप शामिल है। मदर्स रेसिपी सॉस के साथ तैयार किए गए कोरियन फ्राइड राइस और कोरियन वेज डकगाल्बी में बिल्कुल उसी स्वाद का आनंद मिलता है, और इस तरह आप घर में मौजूद सामान से ही आप अपनी पसंदीदा कोरियन डिशेज बना सकते हैं। हर रेसिपी को इतने आसान चरणों में समझाया गया है कि कोई भी इसे पूरे भरोसे के साथ बना सके, भले ही वे पहली बार कोरियन स्टाइल का खाना बना रहे हों।

भव्यता से ग्रामीण पत्रकार सम्मेलन हुआ संपन्न, बड़ी तादात में पत्रकारों ने की शिरकत

अलीगढ़। भारतीय प्रेस परिषद से अधिसूचित संगठन ₹अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन एवं ग्रामीण पत्रकार यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीण पत्रकार सम्मेलन अलीगढ़ नुमाइश मैदान में मुक्ताकाश मंच पर सुखबीर शर्मा के संयोजन में संपन्न हुआ` कार्यक्रम का संचालन राहुल वार्ष्णेय एवं अध्यक्षता अखिल भारतीय समाचार-पत्र एसोशिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चंद्र शुक्ला ने की। समारोह में उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों को सम्मान पत्र स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र शाल बैग डायरी पीतल की श्री गणेश प्रतिमा प्रदान कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र सिंह,स्वामी श्री पूणार्नंद पुरी जी महाराज,अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष शर्मा,विधायक खैर सुरेंद्र दिलेर की माता जी रजनी दिलेर ,प्रेस क्लब के महासचिव आर पी शर्मा ,भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चंदेल दादा, दैनिक प्रावदा के, मालिक मुद्राक, संपादक सुबोध सुहुद ने दीप प्रज्ज्वलित कियो समारोह को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चंद्र शुक्ल ने देश में व्याप्त समस्याओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए हर सम्भव निराकरण का आश्वासन दिया उन्होंने ने यह भी कहा कि आए दिन पत्रकारों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात की घटनाएं हो रही हैं इस पर गंभीर चिंता ब्यक्त करते हुए घोषणा की कि देश के किसी भी कोने में पत्रकारों पर किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष कुमार शर्मा ने कहा संगठन की शक्ति पारस्परिक एकता से ही सम्भव है। अतः सभी को समाज हित और देश हित में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सशक्त विरोध कर अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष संजय कुमार चतुवेर्दी ने कहा कि कोरोना कल में कोरोना काल में सरकार द्वारा रेलवे रियायत सहित अनेको सुविधाओं से पत्रकारों को वंचित कर दिया गया था,जिनकी बहाली अभी तक नहीं की गई। उन्होंने ने समारोह के माध्यम से सरकार से मांग की कि पत्रकारों को प्राप्त सभी पूर्वत सुविधाएं अविलंब बहाल की जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मीडिया प्रभारी दिवाकर खरे ने पत्रकारों की जिमेदारी की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में पत्रकारों की अहम भूमिका है ग्रामीण पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष सुखबीर शर्मा ने अपने ओजस्वी वक्तव्य में संगठन और पत्रकारों के हितों पर अपने विचार रखे हुए सभी साथियों का हर दुःख सुख में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चंदेल ने भी पत्रकारों के कामों की सराहना की। अपने संबोधन में आर पी शर्मा ने कहा पत्रकार कहने को देश का चौथा स्तभ पर सरकार उन्हें अपने स्तर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करती आये दिन पुलिस पत्रकारों को परेशान करती रहती है इसका स्थाई समाधान आवश्यक है इनके अतिरिक्त वरिष्ठ पत्रकार गौरीशंकर शर्मा और अमित अग्रवाल ने भी सम्मेलन को संबोधित किया कार्यक्रम की व्यवस्था में तहसील अध्यक्ष गभाना रामगोपाल उपाध्याय, अतरौली अध्यक्ष केपी राजपूत, इगलास अध्यक्ष बहादुर सिंह, कोल अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा,खैर अध्यक्ष उमेश वर्मन, राकेश गौतम, योगेंद्र सिंह ठेनुआ, प्रेस क्लब खैर के अध्यक्ष कैलाश गोयल, महा सचिव पुनीत गोयल, सत्या पंडित, डाली शर्मा,पंकज शर्मा,अनार सिंह, प्रदीप वार्ष्णेय, पीयूष जादौन, अमित शर्मा, सकुन सिंह, शरद वार्ष्णेय, प्रमोद, राहुल कौशिक, आकाश शर्मा,अनूप यादव, अरुण शर्मा, सुधाकर उपाध्यक्ष के अलावा भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहें । कार्यक्रम में ग्रामीण पत्रकार यूनियन के सैकड़ो सदस्यों को उनके उत्कर्ष कार्यो के लिए सम्मानित किया गया।

आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्रों ने 'प्रोजेक्ट एवरग्रीन' के जरिए रचा इतिहास

मुंबई। भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करते हुए, आईआईटी बॉम्बे ने आज 'प्रोजेक्ट एवरग्रीन' के पूरा होने की घोषणा की। यह पूरी तरह से पूर्व छात्रों द्वारा संचालित एक मुहिम है, जिसके माध्यम से संस्थान की छात्र आवास व्यवस्था (हॉस्टल्स) का कायाकल्प किया गया है। २०० करोड़ रुपये का फंड, तीन अत्याधुनिक हॉस्टल और रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ निर्माण, इन वजहों से 'प्रोजेक्ट एवरग्रीन' ने पूर्व छात्रों के योगदान का वैश्विक स्तर पर एक नया मानक स्थापित किया है।

इस नए परिसर में ८४८ कमरे और १,१२७ बेड हैं, और यह ३,७०,००० वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। यह आईआईटी बॉम्बे के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आवासीय विकास प्रोजेक्ट है। साथ ही, इस प्रोजेक्ट को 'ग्रीन होम्स रेटिंग सिस्टम' के तहत प्रतिष्ठित IGBC गोल्ड रेटिंग मिली है। कैंपस में ऐसी रेटिंग हासिल करने वाली यह पहली इमारत बन गई है, जो टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। इस पहल के बारे में बात करते हुए आईआईटी बॉम्बे के पूर्व निदेशक प्रो. सुभाशिष चौधरी ने कहा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे बुनियादी ढांचे को तत्काल सुधार की आवश्यकता थी और यही वह समय था। यह एक जोखिम लेने जैसा था, लेकिन हमें अपने पूर्व छात्रों के जुनून और प्रतिबद्धता पर पूरा भरोसा था। यह प्रोजेक्ट केवल इमारतें नहीं, बल्कि सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। 'प्रोजेक्ट एवरग्रीन' की शुरूआत पूर्व छात्र स्वयंसेवकों और प्रो. चौधरी के बीच एक साधारण बातचीत से हुई। इसका नेतृत्व नारायण सुंदरेशन (निर्माण प्रमुख) और किरात पटेल (फंडरेज़िंग मॉडल) ने किया। पटेल ने याद दिलाया कि शुरूआत में २६ चार्टर डोनर्स (सनदी दानदाताओं) की मदद से ४-५ करोड़ रुपये का डिजाइन चरण शुरू हुआ और बाद में २,७०० पूर्व छात्रों ने इस विश्वास को सही साबित करते हुए पूरा फंड जुटाया। इस मुहिम में १९६२ के बैच से लेकर २०२४ के बैच तक के २,७०० से अधिक पूर्व छात्रों ने १० रुपये से लेकर १० करोड़ रुपये तक का योगदान दिया। लगभग १०० पूर्व छात्रों ने अपना समय और तकनीकी कौशल निःशुल्क दिया। विशेष रूप से, एक वर्तमान छात्र द्वारा दी गई १०० रुपये की प्रतीकात्मक दान राशि इस अभियान में एकजुटता को दशार्ती है। संस्थान के वर्तमान निदेशक प्रो. शिरीष केदारे ने इस सफलता की सराहना करते हुए कहा कि, ₹प्रोजेक्ट एवरग्रीन न केवल हॉस्टल का स्तर सुधारता है, बल्कि पूर्व छात्र और संस्थान के एक साथ आने पर क्या हासिल किया जा सकता है, यह इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह राष्ट्र निर्माण का एक जीवंत उदाहरण है। २५ से अधिक कॉर्पोरेट कंपनियों ने भी इस प्रोजेक्ट में भागीदारी करके सार्वजनिक-निजी सहयोग का एक आदर्श मॉडल पेश किया है।